● वर्ष-3
● अंक-187
रायपुर, गुरुवार
14 मार्च 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› इस शिव मंदिर के पत्थरों ....

भाजपा ने लोकसभा की सभी 11 सीटें जीतने का किया दावा

विष्णुदेव के तीन महीने का दम

रायपुर। छत्तीसगढ़ की बीजेपी के विष्णुदेव साय सरकार के तीन महीने पूरे हो चुके हैं. इन तीन महीनों में विष्णुदेव साय सरकार ने मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए कई महतारी वंदन योजना, कृषक उन्नति योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना, 3100 रुपये में धान खरीदी, 18 लाख पीएम आवास,रामलला मंदिर दर्शन योजना लागू हो चुकी है, वहीं पीएससी परीक्षा घोटाले में सीबीआई जांच की अनुशंसा प्रमुख रूप से शामिल हैं।

इसके अलावा भाजपा ने 1,000 किमी लंबी शक्तिपीठ परियोजना, रामलला मंदिर दर्शन योजना, तेंदूपत्ता संग्राहकों को 5500 रुपये, बिरनपुर सीबीआई जांच, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को हर वर्ष 10 हजार रुपये की सहायता,दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन, दो साल धान का बकाया बोनस, पांच सालों तक गरीब परिवारों को फ्री में चावल, पत्ता संग्राहकों को 4500 रुपये बोनस पर भी मुहर लगा दी है। भाजपा पदाधिकारियों के मुताबिक सरकार ने 100 दिनों की कार्ययोजना बनाकर जिम्मेदारी बांट दी है। इसी आधार पर मंत्रिमंडल ने भी योजनाओं को पूरा करने की रणनीति बनाई है।

अपनी सरकार के परफॉर्मेंस को देखते हुए बीजेपी का मानना है की छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में सभी 11 की 11 सीटें पार्टी जीतने में इस बार कामयाब हो जाएगी. आपको बता दें कि 8 दिसंबर को हुई मतगणना में जीत हासिल करने के बाद 13 दिसम्बर को विष्णुदेव साय ने दो उप मुख्यमंत्री के साथ शपथ ली थी.

रसोई गैस सब्सिडी का इंतजार

गारंटियों में अभी भी रसोई गैस में 500 रुपये की छूट का इंतजार महिलाओं को हैं। छात्रों के लिए मासिक ट्रैवल अलाउंस, भ्रष्टाचार के खिलाफ आयोग का गठन का वादा पूरा होना बाकी है। भाजपा सूत्रों के मुताबिक रसोई गैस को लेकर एलपीजी कंपनियों से चर्चा जारी है। शीघ्र ही इस गारंटी पर भी मुहर लगेगी।

किसानों को सबसे ज्यादा फायदा

राज्य में भाजपा सरकार ने अपनी गारंटियों में किसानों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा है। 24.72 लाख किसानों के खाते में 12 मार्च को धान खरीदी की अंतर की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी गई। सरकार ने इसके लिए 13320 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। इससे पहले किसानों को दो वर्ष के धान के बोनस के रूप में 3716 करोड़ रुपये व धान खरीदी के एवज में 30 हजार 68 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

महतारी वंदन योजना से बढ़ा भरोसा

विष्णु देव साय ने 3 महीने में प्रधानमंत्री मोदी की कई गारंटियों पूरा करने में सफल रहे हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को इसका सीधा फायदा मिलेगा. चुनावी वादों के मुताबिक, प्रदेश में महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुकी है. चुनाव से पहले 68 लाख महिलाओं के खाते में 1 हजार रुपये डाले जा चुके हैं. दरअसल, विधानसभा के पहले बीजेपी ने महतारी वंदन योजना का वादा किया था, जिससे बीजेपी को महिलाओं ने पूरा समर्थन दिया था. अब इस वादे को पूरा करने के बाद बीजेपी का ये मानना है कि लोकसभा चुनाव में महतारी वंदन योजना की लाभार्थी महिलाएं एक बार फिर से पार्टी का साथ देंगी.

किसानों के खाते में 13200 करोड़ किए ट्रांसफर

विष्णुदेव सरकार ने अपने तीन महीने के कार्यकाल में अहम फैसला लेते हुए किसानों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए राज्य के 24 लाख 75 हजार किसानों को 13 हजार 200 करोड़ की राशी सीधे किसानों के खाते में ट्रान्सफर कर चुकी है. दरअसल, चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने वादा किया था कि बीजेपी की सरकार बनने पर किसानों को एक एकड़ पर 21 क्विंटल धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा जाएगा, जिसे सरकार ने पूरा कर दिया है.

रामलला योजना दर्शन योजना शुरू की गई

छत्तीसगढ़ की विष्णु देव सरकार ने अपने कोर वोटर्स पर पकड़ बरकरार रखने के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू की है, जिसके तहत प्रदेशवासियों को अयोध्या राम मंदिर के दर्शन कराए जा रहे हैं. इस योजना के तहत तीर्थ यात्रियों को अयोध्या आने-जाने, रहने और खाना की पूरी व्यवस्था सरकार करती है. इस योजना के तहत 20 हजार लोगों को हर साल अयोध्या दर्शन कराया जाएगा.

यूपीएससी की तर्ज पर होगी सीजीपीएससी

विष्णुदेव सरकार ने युवा वोटरों को रिझाने के लिए मोदी गारंटी के एक और वादे को पूरा करते हुए यूपीएससी की तर्ज पर सीजीपीएससी की परीक्षाएं कराने के लिए आयोग का गठन किया है. यह आयोग संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर सीजीपीएससी को पारदर्शी बनाने के लिए सुझाव देगा. इसके साथ ही विभिन्न विभागों के लिए परीक्षा आयोजन का वार्षिक कैलेण्डर बनाने और परीक्षार्थियों में आयोग के प्रति विश्वसनीयता बनाए जाने के लिए सुझाव देगा. आयोग का गठन पूर्व अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग प्रोफेसर डॉ. प्रदीप कुमार जोशी की अध्यक्षता में किया गया है.

अर्थ खनिज के एक्सप्लोरेशन लायसेंस के लिए नोटिस इनवाइटिंग टेंडर जारी

मुख्यमंत्री साय-उप मुख्यमंत्री साव की उपस्थिति में जारी किया गया टेंडर

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा मुख्यमंत्री निवास में आयोजित एक संक्षिप्त समारोह में कोंडागांव, नारायणपुर और बस्तर जिले में डायमंड तथा सामरिक महत्व के रेयर अर्थ खनिज के तीन ब्लॉक का ई-नीलामी के माध्यम से एक्सप्लोरेशन लाइसेंस आबंटन के लिए एनआईटी (नोटिस इनवाइटिंग टेंडर) जारी किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरूण साव, खनिज विभाग के सचिव पी दयानंद, संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म सुनील जैन सहित संबंधित अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

गौरतलब है कि देश में क्रिटीकल एवं सामरिक महत्व के खनिजों के अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा खनिज अधिनियम में नवीन संशोधन किया गया है। जिसके फलस्वरूप आरईई, लीथियम, कॉपर, सिल्वर, डायमण्ड, गोल्ड सहित 29 खनिजों के अन्वेषण में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिवर्स बिडिंग के आधार पर एक्सप्लोरेशन लायसेंस आबंटन करने की व्यवस्था की गई है। अन्वेषण उपरांत उक्त ब्लॉक का खनिपट्टा के रूप में ई-नीलामी के माध्यम से फारवर्ड बिडिंग की जाएगी। खनिपट्टाधारी से प्राप्त प्रीमियम में ब्लॉक के एक्सप्लोरेशन लायसेंसी होल्डर का शेयर रहेगा। क्रिटिकल एंड स्ट्रेटजिक मिनरल्स की आवश्यकता रिन्यूवेबल एनर्जी, रक्षा, कृषि, फर्मासिट्यूकल, उच्च-तकनीकी इलेक्ट्रानिक्स, दूरसंचार, परिवहन आदि क्षेत्रों में होती है। इन खनिजों के मामलों में वर्तमान में देश आयात पर निर्भर है। खनिज विभाग के सचिव श्री पी. दयानंद ने इस अवसर पर कहा कि देश में सामरिक महत्व के खनिजों की आपूर्ति, आयात निर्भरता में कमी एवं राजस्व की दृष्टि से डीपसीटेड ऐसे बहुमूल्य खनिजों के विकास हेतु यह व्यवस्था अत्यंत प्रगतिशील एवं महत्वपूर्ण है। खनिज विभाग के विशेष सचिव सुनील जैन ने बताया कि विभाग द्वारा गत वर्ष ग्रेफाईट, ग्लूकोनाईट, निकल क्रोमियम पीजीई, गोल्ड के 08 ब्लॉक्स का सफलतापूर्वक आबंटन किया गया। वहीं कटघोरा (कोरबा) में लीथियम भंडार की नीलामी प्रक्रिया जारी है। इस विभागीय प्रयास पर भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को 'बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड' से नवाजा गया है। एनआईटी लॉचिंग समारोह में संयुक्त संचालक एवं नोडल अधिकारी ऑक्शन, अनुराग दीवान सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

भाजपा की दूसरी सूची में 72 नामों की घोषणा

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार (13 मार्च) को उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है. बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 72 नामों का ऐलान किया गया है. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को महाराष्ट्र की नागपुर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है. गडकरी इसी सीट से मौजूदा सांसद हैं. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और हरियाणा के सीएम पद से एक दिन पहले इस्तीफा देने वाले मनोहर लाल खट्टर को भी टिकट दिया गया है. खट्टर हरियाणा के करनाल से चुनाव लड़ेंगे. जबकि पीयूष गोयल को मुंबई नॉर्थ और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को हिमाचल के हमीरपुर से टिकट मिला है. केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी कर्नाटक के धारवाड़ से चुनाव लड़ेंगे. बीजेपी इससे पहले 2 मार्च को 195 सीटों पर कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया था. इस तरह अब तक 267 सीटों पर नामों की घोषणा की जा चुकी है.

करनाल से खट्टर तो सिरसा से अशोक तंवर

करनाल से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को उम्मीदवार बनाया गया है. मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, इसके बाद बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को सूबे की कमान सौंप दी. इसके साथ ही पार्टी ने जेजेपी के साथ अपना गठबंधन भी तोड़ लिया. दूसरी ओर सिरसा से अशोक तंवर को टिकट दिया गया है. अशोक तंवर साल 2009 के लोकसभा चुनाव में यह सीट कांग्रेस की टिकट पर जीत चुके हैं. बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया था. फिर आम आदमी पार्टी छोड़कर वह बीजेपी में पहुंचे थे.

अंबाला (एससी) सीट से बंतो कटारिया ठोकेंगी ताल

अंबाला (एससी) सीट से बंतो कटारिया को उम्मीदवार बनाया या है. बंतो 2019 में चुनाव जीतने वाले रतन लाल कटारिया की पत्नी हैं, जिनकी साल 2023 में मौत हो गई थी. भिवानी-महेंद्रगढ़ (चौधरी धर्मबीर सिंह), गुड़गांव (चौधरी इंद्रजीत सिंह यादव) और फरीदाबाद (कृष्ण पाल गुर्जर) से मौजूदा सांसदों को ही उम्मीदवार बनाया गया है.

मध्य प्रदेश की बाकी बची 5 सीटों के लिए भी उम्मीदवारों का ऐलान

मध्य प्रदेश की 29 में से शेष 5 लोकसभा सीटों के लिए भी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है. बालाघाट से डॉ. भारती पारधी, छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू, उज्जैन (एससी) से अनिल फिरोजिया, धार (एसटी)से सावित्री ठाकुर और इंदौर से शंकर लालवानी को उम्मीदवार बनाया है. दूसरी लिस्ट में इंदौर से शंकर लालवानी, उज्जैन से अनिल फिरोजिया को फिर से टिकट मिला हैं. वहीं, धार से मौजूदा सांसद छतर सिंह दरबार और बालाघाट से ढाल सिंह बिसेन का टिकट काटा गया है. छिंदवाड़ा से 2019 लोकसभा चुनाव में नाथन शाह को टिकट दिया गया था, लेकिन वह नकुलनाथ से हार गए थे. बीजेपी ने मध्य प्रदेश में कुल छह महिलाओं को लोकसभा चुनाव का टिकट दिया गया.

वरिष्ठ कांग्रेस नेता पद्माकर वलवी भाजपा में हुए शामिल

मुंबई। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका देते हुए, पार्टी के वरिष्ठ नेता पद्माकर वलवी बुधवार को महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए। उन्होंने मुंबई में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चन्द्रशेखर बावनकुले और पार्टी नेता अशोक चव्हाण की मौजूदगी में पाला बदल लिया। नंदुरबार में शहादा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व विधायक वलवी, पहले राज्य में खेल मंत्री का पद संभाल चुके थे और उत्तरी महाराष्ट्र में सबसे पुरानी पार्टी के भीतर एक उल्लेखनीय व्यक्ति थे। 2009 में वाल्वी ने महाराष्ट्र विधान सभा चुनाव में शहादा निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की। हालांकि, 2014 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वलवी के भाजपा में शामिल होने की अटकलें पिछले दो वर्षों से चल रही थीं। वलवी का दल बदलने का निर्णय एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आता है क्योंकि एनडीए और आई.एन.डी.आई.ए दोनों गुट पार्टियां वर्तमान में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में महाराष्ट्र के लिए सीट-बंटवारे के फॉर्मूले पर चर्चा कर रही हैं।

प्रमुख समाचार

5 दिवसीय यात्रा पर भारत आएंगे भूटान के प्रधानमंत्री

नई दिल्ली। भूटान के प्रधान मंत्री शेरिंग टोबगे जनवरी में शीर्ष कार्यालय का कार्यभार संभालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा में गुरुवार से भारत की पांच दिवसीय यात्रा पर आएंगे। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने 14 से 18 मार्च तक भूटानी नेता की यात्रा की घोषणा करते हुए कहा कि टोबगे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यापक वार्ता करेंगे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। भूटानी नेता का मुंबई जाने का भी कार्यक्रम है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भूटान के प्रधान मंत्री की यात्रा दोनों पक्षों को हमारी अनूठी साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करने और भारत और भूटान के बीच मित्रता और सहयोग के स्थायी संबंधों का विस्तार करने के तरीकों और साधनों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगी। टोबगे के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आएगा जिसमें भूटानी विदेश और विदेश व्यापार मंत्री, ऊर्जा मंत्री और उद्योग और वाणिज्य मंत्री शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और भूटान के बीच सभी स्तरों पर विश्वास, सद्भावना और आपसी समझ पर आधारित मित्रता और सहयोग के अनुकरणीय संबंध हैं।

जम्मू-कश्मीर में चुनाव को लेकर तैयारी तेज

नई दिल्ली। अंतराल के बाद कश्मीर में राजनीतिक गर्मी नजर आ रही है। चुनाव आयोग ने चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए घाटी में राजनीतिक दलों के साथ बातचीत की है। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों ने लोकसभा के साथ राज्य विधानसभा चुनाव कराने की मांग की है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार तीन दिन के दौरे पर नजर आए जहां वो लोगों और राजनीतिक पार्टियों से रायशुमारी की है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए चीफ इलेक्शन कमीशनर राजीव कुमार अपनी टीम के साथ घाटी पहुंचे और लगातार बैठकों का दौरा चलता रहा। सबसे पहले राजनीतिक दलों से चुनाव आयोग की टीम ने मुलाकात की है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हम यहां जम्मू-कश्मीर और पूरे देश में शांतिपूर्वक और अधिकतम भागीदारी के साथ चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। आगामी लोकसभा चुनावों के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में चुनाव तैयारियों की समीक्षा पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हमने भाजपा, सीपीआईएम, कांग्रेस और एनसी, पीडीपी जैसी राज्य मान्यता प्राप्त पार्टियों से मुलाकात की।

देशभर में किसान 16 मार्च से निकालेंगे अस्थि कलश यात्रा

पटियाला (पंजाब)। संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और भारतीय किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा ने 16 मार्च से देश के विभिन्न राज्यों में अस्थि कलश यात्रा निकालने का एलान किया है। इसके लिए

शुक्रवार को किसान नेता अपने समर्थकों के साथ बठिंडा के गांव बल्लों जाएंगे। यहां से शुभकरण की अस्थियों के 21 कलश तैयार करके इन्हें पहले शंभू और खनौरी सीमा पर ले जाएंगे। इसके बाद 16 मार्च से हरियाणा से अस्थि कलश यात्रा की शुरुआत होगी। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल ने बताया कि यह यात्रा हरियाणा के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तामिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गुजरात और राजस्थान राज्यों में भी निकाली जाएगी। यह यात्रा गांव-गांव जाएगी और इस दौरान लोगों को केंद्र की किसान विरोधी नीतियों के बारे में जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा किसानों की मांगों के समर्थन में आगे आने को प्रेरित किया जाएगा। किसान नेताओं ने आगे बताया कि हरियाणा में अस्थि कलश यात्रा के दौरान 22 मार्च को हिसार जिले के ऐतिहासिक स्थान माजरा पिआउ में और इसके बाद 31 मार्च को अंबाला के मौड़ा मंडी में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया जाएगा।

संजय निरुपम का कांग्रेस छोड़ने, भाजपा में जाने की चर्चा

मुंबई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के महाराष्ट्र आते ही कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री पद्माकर वलवी ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा, क्या इसके बाद कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगेगा? ऐसी चर्चाएं तब शुरू हो गई हैं जब संजय निरुपम ने अशोक चव्हाण से मुलाकात की है। उद्धव ठाकरे द्वारा अमोल कीर्तिकर को मुंबई उत्तर-पश्चिम लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित करने के बाद संजय निरुपम नाराज हैं। संजय निरुपम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी नाराजगी जाहिर की है। लेकिन अब खबर है कि संजय निरुपम ने अपने पुराने सहयोगी और बीजेपी सांसद अशोक चव्हाण से मुलाकात की है। इस दौरे से राजनीतिक गलियारों में चर्चा छिड़ गई है। संजय निरुपम ने मंगलवार रात अशोक चव्हाण से उनके आवास पर मुलाकात की है। हालाँकि बातचीत का विवरण अभी भी गुप्त है, अगर संजय निरुपम ने कोई अलग निर्णय लिया, तो महाविकास अघाड़ी को नुकसान हो सकता है। इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर कोई विकास के लिए आ रहा है तो उनका स्वागत है।

सीएए जुमलेबाज़ी, बंगाल में इजाजत नहीं देंगे: ममता

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नव अधिसूचित नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) पर ताजा हमला करते हुए कहा कि वह असम की तरह बंगाल में भी डिटेंशन कैंप नहीं चाहतीं। तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि सीएए एनआरसी से संबंधित है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। हम असम की तरह डिटेंशन कैंप नहीं चाहते। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हमारा काम है जनता से कहना है। भाजपा का काम है जुमलेबाज़ी है। उन्होंने(बीजेपी) ने कहा कि हमें 400 सीट मिलेंगे। हम ऐसा नहीं कह सकते, हम जनता के ऊपर सब छोड़ते हैं, जनता जिसे वोट देगी हम उसे मानेंगे लेकिन भाजपा जबरदस्ती से चुनाव करेगी तो हम इसे नहीं मानेंगे। सीएए पर अपना हमला जारी रखते हुए बनर्जी ने इस कानून को लोकसभा चुनाव से पहले एक %राजनीतिक हथकंडा% करार दिया। कानून के अनुसार, केंद्र अब बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करना शुरू कर देगा। इनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शामिल हैं।

इतनी भगदड़ के बाद भी कांग्रेस नेतृत्व के रवैये में बदलाव नहीं

रशीद किदवई

वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में धूमिल संभावनाओं को देखते हुए कांग्रेस एक विखंडित पार्टी के रूप में नजर आ रही है। वर्ष 2014 लेकर अब तक पार्टी ने 50 से ज्यादा प्रभावशाली नेताओं, जिनमें 15 मुख्यमंत्री और इतने ही पूर्व केंद्रीय मंत्री, एआईसीसी पदाधिकारी और अन्य प्रतिष्ठित लोग शामिल हैं, को बाहर निकलते देखा है। पिछले दस वर्षों में पंद्रह पूर्व मुख्यमंत्रियों के पार्टी से बाहर जाने के बावजूद एक भी मामले में कांग्रेस नेतृत्व ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि इतने सारे वरिष्ठ और दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं। इंदिरा गांधी को दो बार 1969 एवं 1977 में ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने अपने विरोधियों को परास्त कर बाजी पलट दी।

यहां तक कि जब 1987 में राजीव गांधी का पतन शुरू हुआ, तो कई नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में जनमोर्चा के गठन के लिए पार्टी छोड़कर चले गए। नरसिंह राव के कार्यकाल में अरुण सिंह, एनडी तिवारी, एस बंगरप्पा, माधवराव सिंधिया और ममता बनर्जी पार्टी जैसे नेता पार्टी से बाहर हो गए। वर्ष 1999 में शरद पवार ने अपनी अलग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई। लेकिन 2014 के बाद कोई विभाजन नहीं हुआ, जो थोड़ा असामान्य है। क्या ऐसा इसलिए है, क्योंकि वर्तमान कांग्रेस नेता अलग हुए समूहों को राजनीतिक रूप से व्यावहारिक नहीं पाते हैं? या फिर ऐसी भावना है कि कांग्रेस की विचारधारा को कोई अपनाने वाला नहीं है, इसलिए विपरीत खेमे यानी भाजपा में शामिल होना ही समझदारी है?

पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को दोष देने के बजाय कांग्रेस को अपने वैचारिक ढांचे को मजबूत करना होगा और 'क्या करें' तथा 'क्या नहीं करें' की एक सूची बनानी होगी। लेखक जहीर मसानी ने एक बार पूर्व प्रधानमंत्री को उद्धृत करते हुए कहा था कि कोई %व्यक्ति जो राष्ट्र प्रमुख हो, वह व्यावहारिक न होने का जोखिम भला कैसे उठा सकता है। आपको हर दिन व्यावहारिक बनना पड़ता है। लेकिन आपको अपनी व्यावहारिकता को किसी प्रकार के आदर्शवाद से जोड़ना होगा, अन्यथा आप जो करना चाहते हैं, उसके लिए लोगों को उत्साहित नहीं कर पाएंगे।% राहुल की कांग्रेस में पार्टी की विचारधारा लोगों को उत्साहित करने में विफल रही है।

जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, जाति आधारित जनगणना, खून की दलाली, चौकीदार चोर है जैसी राहुल की टिप्पणियों और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से इन्कार ने पार्टी विचारधारा को मजबूत बनाया है। दिवंगत वीएन गाडगिल ने कहा था कि भावनात्मक मुद्दों पर कांग्रेस दो पाटों के बीच फंस गई है। इसके अलावा, राहुल गांधी गैर-परंपरागत और लापरवाह नेता के रूप में दिखते हैं। पूर्व कांग्रेस प्रमुख के रूप में राहुल लाखों कांग्रेस कार्यकर्ताओं, समर्थकों और मतदाताओं की भावनाओं और संवेदनाओं को उचित महत्व दिए बिना अपने अधिकार की भावना से ग्रस्त दिखे।

ऐतिहासिक रूप से अपने राजनीतिक अभियानों में धर्म को मिलाने की कांग्रेस की कोशिश समस्याग्रस्त रही है। धर्म एवं राजनीति को लेकर जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के विचारों में भारी विरोधाभास थे। महात्मा गांधी के लिए धर्म धर्मनिरपेक्षता का अभिन्न हिस्सा था। गांधी कहते थे कि धर्म रहित राजनीति पूरी तरह गंदगी है। राहुल गांधी का मुस्लिम बुद्धिजीवियों को शामिल करने का कदम, शशि थरूर की भारत के हिंदू पाकिस्तान में बदलने की आशंका और 2019 में कांग्रेस के घोषणापत्र में जम्मू-कश्मीर से सुरक्षा बलों को आंशिक रूप से वापस बुलाने की पेशकश का नकारात्मक असर हुआ।

कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची सांगठनिक उद्देश्यों के बजाय व्यक्तिगत हितों से प्रेरित लगती है। उदाहरण के लिए, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हाल ही में विधायक चुने जाने के बावजूद राजनंदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं। बघेल की योजना के अनुसार, राजनंदगांव से जीत जाने पर वह कांग्रेस के एक विश्वसनीय पिछड़े नेता के रूप में सामने आएंगे। दूसरी तरफ, राजस्थान में अशोक गहलोत स्वयं तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन जालौर से अपने बेटे वैभव की उम्मीदवारी पर जोर दे रहे हैं। अलपुझ्झा सीट से एआईसीसी संगठन प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल की उम्मीदवारी देखकर कई कांग्रेसी भी हैरान रह गए। केसीवी फिलहाल राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं और उनका कार्यकाल 2028 तक है। यदि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद वह राज्यसभा सीट छोड़ते हैं, तो वह सीट भाजपा के पास चली जाएगी। कथित तौर पर यदि कांग्रेस 2024 के चुनाव में 55 या उससे अधिक सीटें जीतने में कामयाब होती है, तो केसीवी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने की उम्मीद में चुनाव लड़ रहे हैं। यदि 18वीं लोकसभा में वास्तव में ऐसा होता है, तो कांग्रेस को कुछ और नेताओं के पार्टी छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए।

अंबिकापुर में सरकारी अधिकारियों और भूमाफियाओं का बड़ा खेला

गोचर जमीन को नजूल में बदला फिर कई लोगों को बेचा

सरगुजा। शहर के नमनाकला स्थित सरकारी नजूल जमीन गोचर मद की जमीन है। इस जमीन पर भूमाफियाओं की नजर थी। लिहाजा भूमाफियाओं ने तत्कालीन नजूल अधिकारी के साथ मिलीभगत कर गोचर मद की जमीन को पहले नजूल मद में दर्ज कराया और फिर बंसू लोहार नामक व्यक्ति के नाम पर जमीन दर्ज कराई गई उसके बाद इसकी बंदरबाट कर शहर के कई लोगों को ये जमीन बेच दी।

नमनाकला निवासी बंसू लोहार की मौत 15 साल पहले हो चुकी है। उन्हें साल 1967-68 में नमनाकला में सिंहदेव योजना के तहत पट्टा दिया गया लेकिन साल 1971-72 में नमनाकला की पूरी सरकारी जमीन को नजूल घोषित कर दिया गया। इसमें बंसू की जमीन भी नजूल रिकॉर्ड में आ गई। भूमाफियाओं ने नमनाकला निवासी बंसू लोहार की जगह पर परसा निवासी बंसू लोहार को खड़ा कर फर्जी आधार कार्ड व दस्तावेजों के आधार पर नजूल रिकॉर्ड में त्रुटि सुधार और नामांतरण दर्ज करने का आवेदन लगाया। बड़े पैमाने पर मिलीभगत कर परसा निवासी बंसू लोहार के नाम पर जमीन दर्ज कराने के बाद इस जमीन को सतीश शर्मा, सन्मोगर वारियर, अभिषेक नागदेव, शेखर अग्रवाल, सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल, अनुषा नागदेव, महेश कुमार केडिया और दिनेश कुमार को बेच दी।

इस मामले की शिकायत कलेक्टर के पास की गई। कलेक्टर भोस्कर विलास संदीपान ने मामले की जांच कराई और जांच के दौरान इस बात की पुष्टि हुई कि 4।22 एकड़ सरकारी भूमि (जिसका खसरा नंबर 243/1 और रकबा 1।710) नजूल अधिकारी ने आरआई व भू-माफियाओं के साथ मिलीभगत तक सरकारी जमीन का मद बदला और निजी व्यक्ति के नाम पर किया। इस मामले में कलेक्टर ने बंसू लोहार के साथ ही सतीश शर्मा, सन्मोगर वारियर, अभिषेक नागदेव, शेखर अग्रवाल, सुरेंद्र कुमार अग्रवाल, अनुषा नागदेव, महेश कुमार केडिया और दिनेश कुमार को नोटिस जारी किया। उन्हें 14 मार्च को कलेक्टर न्यायालय में पेश होने का निर्देश भी दिया गया। इधर इस मामले की एसडीएम से भी जांच कराई गई।

सरगुजा कलेक्टर भोस्कर विलास संदीपान ने कहा सरकारी जमीन के फर्जीवाड़ा की शिकायत मिली थी जो सही पाई गई। इस मामले को कलेक्टर न्यायालय में लिया गया है। एसडीएम से मामले की जांच कराई गई और थाने में दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। जांच के बाद दोषियों को सजा भी दी जाएगी। इसके साथ ही जमीन को दोबारा शासकीय मद में दर्ज कर विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए आरक्षित किया जाएगा।

जांच में करोड़ों रुपये के जमीन फर्जीवाड़ा मामले में तत्कालीन नजूल अधिकारी व पूर्व अपर कलेक्टर नीलम टोप्पो की भूमिका भी संदिग्ध मिली। इस बात का भी खुलासा हुआ कि नजूल अधिकारी नीलम टोप्पो ने आरआई नारायण सिंह, आरआई राहुल सिंह, रीडर अजय तिवारी के साथ मिलकर जमीन का मद परिवर्तन करने के साथ ही फर्जी दस्तावेज के आधार पर हेराफेरी की। इस मामले में कलेक्टर के निर्देश पर नजूल अधिकारी ने गांधीनगर थाना में शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद गांधीनगर पुलिस ने तत्कालीन नजूल अधिकारी समेत चारों अधिकारियों के खिलाफ धारा 467, 468, 420, 120 बी के तहत केस दर्ज किया।

अवैध रेत परिवहन, 24 घंटे रेत ट्रांसपोर्ट को नहीं देख सकता : माइनिंग अधिकारी

बलौदाबाजार-भाटापारा। बलौदाबाजार भाटापारा में अवैध रेत परिवहन पर खनिज विभाग के सुस्त रवैये से बिना रॉयल्टी पर्ची के सैकड़ो हाईवा रेत परिवहन हो रहा है। बलौदा बाजार भाटापारा एक ऐसा जिला है जिसमें रेत माफिया को खुली छूट मिली हुई है कि आप बिना रायल्टी पर्ची के चाहे जितना रेत घाट से रेत निकाल लो बस इतना ध्यान रहे कि आपकी पहुंच किसी सफेद पोषकधारी एवं रासुखदार तक होनी चाहिए।

भाटापारा से जब रेत भरी गाड़ियां निकलती है तो खनिज विभाग तो कार्यवाही पर नजर में नहीं आती हैं, लेकिन धोखे से किसी पुलिस की नजर पड़ जाती है तथा जांच के लिए रोक कर कागजात पत्र मांगा जाता है तो कुछ हाइवा चालक कागज पत्र तो दिखा देते हैं ,लेकिन कुछ वाहन चालक सफेद पोषकधारी से संबंध रखने वाले सीधे सफेद पोषकधारी के मोबाइल से बात करते हैं तो कुछ रसूखदारों से जिससे कार्यवाही के लिए रेत गाड़ी का रायल्टी पर्ची या अन्य दस्तावेज जांच करने वाले पुलिस के अधिकारी कर्मचारी सफेद पोशाक धारी एवं रसूखदारों का सम्मान करते हुए बिना रायल्टी पर्ची ,बिना दस्तावेज वाले गाड़ी को छोड़ दिया जाता है। यह खेल भाटापारा में जोरों से चल रहा है, जब इस संबंध में माइनिंग अधिकारी भक्त से बात की गई तो उन्होंने कहा बिना रॉयल्टी पर्ची बिना दस्तावेज वाले गाड़ी में पुलिस कार्यवाही कर सकती है ,तहसीलदार कार्यवाही कर सकता है, और आरटीओ ओवरलोड की कार्यवाही कर सकती है अगर पुलिस विभाग छोड़ रही है तो मैं क्या कर सकता हूं , जब अधिकारी भक्त से पूछा गया रेत घाट से बीना रायल्टी पर्ची के गाड़ी बाहर कैसे निकल जाती है? तो उन्होंने कहा यह तो ट्रांसपोर्टर की वजह से हो सकता है ट्रांसपोर्टर की गलती है अगर रायल्टी नहीं ले रहा है या रायल्टी पर्ची नहीं दे रहा है। जब अधिकारी से पूछा गया इस तरह शासकीय क्षति हो रही है उस पर क्या कार्यवाही करना उचित नहीं है? तो माइनिंगअधिकारी भक्त ने कहा कार्यवही तो होनी चाहिए अगर बिना रॉयल्टी के रेत गाड़ी मिलती है तो ,पुलिस को कार्यवाही करनी चाहिए। तहसीलदार भी कार्यवाही कर सकता है, हमारे द्वारा बिना पर्ची की गाड़ी को पड़कर कार्रवाई की जाती है मैं दिन भर फील्ड में नहीं रह सकता और ना ही 24 घंटे अवैध रेत ट्रांसपोर्ट को देख सकता हूं ऑफिस में और भी काम रहता है।

कवर्धा नगर पालिका में हंगामा

कांग्रेस के पास बहुमत फिर भी भाजपा पार्षद बने कार्यवाहक अध्यक्ष

कबीरधाम। कबीरधाम जिले के कवर्धा नगर पालिका कार्यालय में बुधवार को बवाल हो गया। कांग्रेस पार्षदों ने नए अध्यक्ष की नियुक्ति व उनके बिना अनुमति के पीआईसी कमेटी में शामिल किए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। यहां कांग्रेस पार्षद और अध्यक्ष रहे ऋषि शर्मा ने दिसंबर माह में अपना इस्तीफा दिया था। इसके बाद अध्यक्ष का पद रिक्त था। एक दिन पहले मंगलवार को राज्य सरकार ने भाजपा पार्षद मनहरण कौशिक को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है।

मंगलवार को उन्होंने पद की शपथ लिया है। नगर पालिका में कुल 27 वार्ड है, जिसमें 19 में कांग्रेस व 6 में भाजपा व एक में निर्दलीय पार्षद है।

कांग्रेस पार्षदों का दावा है कि उनके पास पूर्ण बहूमत है, इसके बाद भी भाजपा के पार्षद को अध्यक्ष बनाया जाना गलत है। इसी से नाराज कांग्रेस पार्षदों ने सीएमओ को जूते चप्पल की माला भेंट करने पहुंचे हुए थे। इससे पहले पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ता और पार्षद को कार्यालय के बाहर रोक लिया। इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई।

पार्षद अरूणधति चन्द्रवंशी, महिमा गुप्ता, संतोष यादव, उत्तम गोप, जानकी जायसवाल, सुष्मा सिन्हा, सुशीला धुर्वे ने बताया कि सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता व पार्षद हैं। आज बुधवार की सुबह 10 बजे हमे नगर पालिका से जारी पत्र में सलाहकार समिति के सदस्य बनाए जाने की जानकारी प्राप्त हुई। हम सभी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। सीएमओ द्वारा जबरदस्ती बिना अनुमति व सहमति के हमे पीआईसी सलाहकार सदस्य बनाकर बदनाम करने का प्रयास किया गया।

कांग्रेस पार्षदों ने आगे कहा कि हम सभी पीआईसी का सलाहकार सदस्य नहीं बनना चाहते। कांग्रेस पार्षद मोहित माहेश्वरी ने बताया कि नए कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति गलत है। पहले दिन से ही विरोध कर रहे हैं।

जशपुर से नक्सली एरिया कमांडर टुनेश लकड़ा साथियों के साथ हुआ गिरफ्तार

जशपुर। जशपुर और बलरामपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने जेजेएमपी (झारखंड जन मुक्ति परिषद) एरिया कमांडर टुनेश लकड़ा उर्फ रवि के साथ छह नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। टुनेश लकड़ा के खिलाफ बलरामपुर जिले के विभिन्न थानों के अलावा झारखंड के विभिन्न थानों में हमला/मुठभेड़, डकैती, आगजनी, अपहरण के कुल 31 अपराध दर्ज हैं।

झारखंड पुलिस से सूचना प्राप्त हुई कि बलरामपुर एवं जशपुर क्षेत्र में टुनेश लकड़ा उर्फ रवि अपने अन्य साथियों के साथ छिपा हुआ है, उसके पास आधुनिक हथियार है। इस सूचना पर पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज ने जशपुर पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह और बलरामपुर पुलिस अधीक्षक डॉ। लाल उम्मेद सिंह को तत्काल टीम का गठित कर संयुक्त ऑपरेशन चलाने का निर्देश दिया।

कुनकुरी एसडीओपी विनोद मण्डावी और बलरामपुर जिला में पदस्थ एएसआई सुभाष कुजूर की अगुवाई में पुलिस टीम ने जशपुर जिले के ग्राम करमा थाना नारायणपुर एवं कुनकुरी में दबिश देकर उक्त सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई। आरोपियों के कब्जे से एक नग एके-47, एक नग मैग्जीन जिंदा राउण्ड 90, एक चापड़, नक्सली ड्रेस एवं अन्य दैनिक उपयोगी सामग्री जप्त किया गया है।

जशपुर जिला के थाना नारायणपुर के ग्राम करमा से नक्सल सदस्य राम लकड़ा (40 साल) निवासी गढ़िया थाना भण्डरिया (झारखंड), रंजीत महतो (30 साल) निवासी ओरगी थाना विष्णुगढ़ (झारखंड) और हेरमन कुमार गन्नुम निवासी टिकैतबंध थाना मुण्डा चतरा (झारखंड) को गिरफ्तार किया गया है। वे करमा ग्राम में किरायेदार के रूप में विगत सप्ताह से निवासरत थे। वहीं गुलाम शहजादा को उसके निवास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर दबिश देकर कुनकुरी से जेजेएमपी सरगना टुनेश लकड़ा उर्फ रवि को उसके साथी तबस्सुम अहमद के साथ गिरफ्तार किया गया है। चोरी के प्रकरण में जेल जा चुका आरोपी तब्सुम अहमद मोहम्मद सद्दाम के मकान में किराये पर निवासरत था।

आरोपियों के लगातार संपर्क में रहने वाले तबस्सुम अहमद इनके लगातार संपर्क में था, और उसने बलरामपुर क्षेत्र से टुनेश लकड़ा उर्फ रवि को लाकर कुनकुरी में साथी के रूप में रखा था। टुनेश लकड़ा उर्फ रवि वर्तमान में झारखंड के जिला गढ़वा एवं छत्तीसगढ़ के जिला बलरामपुर के सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय है। इसके विरूद्ध जिला बलरामपुर में 13 प्रकरण एवं झारखंड में 18 प्रकरण कुल 31 प्रकरण पंजीबद्ध है।

शहर की सड़कों पर देर रात पैदल निकले पुलिस अधीक्षक

संजय मार्केट और इलाके का किया औचक निरीक्षण

जगदलपुर। जगदलपुर शहर के व्यस्तम भीड़भाड़ वाले इलाके में बीती रात को पुलिस अधीक्षक अपनी टीम के साथ पैदल निरीक्षण के लिए निकले। इस दौरान पुलिस सहायता केंद्र से लेकर अन्य हिस्सों में पैदल ही घूमते हुए शहर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया।

बस्तर पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा द्वारा जिले के सबसे ज्यादा भीड़ वाले क्षेत्रों में यातायात, पार्किंग तथा अन्य असुविधाओं को देखते हुए पैदल पेट्रोलिंग किया गया, पुलिस अधीक्षक द्वारा जगदलपुर के संजय मार्केट तथा पुलिस चौकी का औचक निरीक्षण किया गया, चौकी निरीक्षण के दौरान चौकी के साफ-सफाई पर नियमित रुप से ध्यान देने कहा गया, संजय मार्केट के निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा पैदल चलकर पूरे मार्केट का जायजा लिया गया।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बताया की संजय मार्केट शहर का मुख्य मार्केट है जहां हमेशा भीड़ एवम ट्रैफिक की समस्या बनी रहती है, मार्केट में भीड़ होने का फायदा उठाते हुए पॉकेटमारी की शिकायतें आती रहती हैं, जिसे देखते हुए मार्केट में सिविल तथा वर्दीधारी ड्युटी के साथ साथ ट्रैफिक के जवानों को भी ड्यूटी के लिए बताया गया, साथ ही जनता से अच्छे पुलिस आचरण करने को कहा गया। संजय मार्केट के साथ ही साथ बस स्टैंड पुलिस सहायता केन्द्र, थाना बोधघाट का भी निरीक्षण किये, इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग, डीएसपी ट्रैफिक संतोष जैन, थाना प्रभारी कोतवाली लीलाधर राठौर एवं चौकी प्रभारी एएसआई अविनाश झा के अलावा अन्य अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़

बीजापुर। बीजापुर जिले के नक्सल प्रभावित बोड़गा के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ की क्रॉस फायरिंग की चपेट में आकर एक महिला जख्मी हो गई है। जख्मी महिला को जवानों ने सीएचसी लाकर उपचार कराया। यहां से उसे बेहतर इलाज के लिए डिमरापाल जगदलपुर रेफर किया गया है। पुलिस ने बताया कि बोड़गा के जंगल मे भैरमगढ़ एरिया कमेटी के नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर मंगलवार को डीआरजी व एसटीएफ की संयुक्त पार्टी बोड़गा ताकीलोड़ व उसपरि की ओर निकली हुई थी। बुधवार की दोपहर तीन बजे के करीब बोड़गा के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के क्रॉस फायरिंग की चपेट में आने से बोड़गा निवासी 44 वर्षीय महिला राजे ओयाम को गोली लगने से वह घायल हो गई। पीड़ित की मदद के लिये जवान पहुंचे और घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भैरमगढ़ में प्राथमिक उपचार कराया। फिर यहां से बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज डिमरापाल जगदलपुर के लिये रेफर कर दिया गया हैं।

दुर्ग जिले में लोकसभा निर्वाचन की तैयारियां शुरू

दुर्ग। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी नें आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु नियुक्त नोडल अधिकारियों की बैठक में अधिकारियों को सौंपे गये दायित्व के अनुसार प्रारंभिक तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिये। उन्होंने निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता के सुव्यवस्थित प्रबंधन, निर्वाचन व्यय अणुवीक्षण, ईवीएम तथा शिकायत सेल, यातायात व्यवस्था, डाकमत पत्र होम वोटिंग, रूटचार्ट वाहन व्यवस्था, विडियोग्राफी सीसीटीवी कैमरा, एमसीएमसी समिति गठन, कर्मचारी कल्याण, ब्रेनलिपि मुद्रण, निर्वाचन प्रशिक्षण, सामग्री वितरण एवं वापसी केन्द्रों मे व्यवस्था और प्रेक्षकगणो के लिये जानकारियां तैयार करने के संबंध में जानकारी ली। कलेक्टर ने सर्व कार्यालय/ विभाग प्रमुख अधिकारियों को अवगत कराया है कि निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा के साथ ही आचार संहिता प्रभावशील हो जायेगी। आचार संहिता लगते ही 24 एवं 48 घंटे के भीतर की जाने वाली कार्यवाही हेतु अभी से चिन्हांकित कर लिया जाये।

लोकसभा चुनाव हेतु उड़नदस्ता दलों का प्रशिक्षण सम्पन्न

बलरामपुर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रिमिजियुस एक्का के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए एफएसटी, एसएसटी, (उड़न दस्ता)टीम का गठन किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में इन समस्त दलों का आज विस्तृत प्रशिक्षण संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में सम्पन्न हुआ। प्रशिक्षण में निर्वाचन के दौरान अवैध रूप से परिवहन किए जाने वाले निर्वाचन सामग्रियों, संपत्ति विरूपण आदि के कार्यवाहियों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। जिसमें आचार संहिता उल्लंघन के मामलों, अवैध रूप से परिवहन किए जाने वाले सामग्रियों एवं मतदाताओं को प्रलोभन के लिए प्रयोग किए जाने वाले गतिविधियों की रोकथाम के लिए की जाने वाली कार्यवाही एवं कानूनी प्रावधानों से अवगत कराया गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अमित श्रीवास्तव, नोडल अधिकारी व्यय श्री संतोष सिंह, सहायक प्रोग्रामर आशीष द्विवेदी, मास्टर ट्रेनर्स श्री विनोद कुर्रे के द्वारा गठित दल के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

मतदाता जागरूकता के तहत ईवीएम का प्रदर्शन

नारायणपुर। लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत् कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बिपिन मांझी के निर्देशानुसार जिले में शतप्रतिशत मतदान कराने हेतु ईवीएम का प्रदर्शन कलेक्ट्रेट परिसर में किया जा रहा है। सभी मतदान केन्द्रों में शतप्रतिशत मतदान कराने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। स्वीप कार्यक्रम के तहत् जिले के सभी बीएलओ को निर्देशित किया गया है कि अपने अपने कार्यक्षेत्र में लोकसभा निर्वाचन में शतप्रतिशत मतदान कराने के लिए घर घर जाकर मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही ईवीएम का प्रदर्शन जिले के सभी हाट बाजारों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, पंचायतों में किया जा रहा है। आज ग्राम कुरूशनार के संतेर, आतर गांव के जुबलराम कोर्राम, लहरूराम कोर्राम, पिड़ियोकोट के मनीराम मण्डावी, फुमलाबाई, छोटेडोंगर के फुलेश्वरी, संजना पवार, संतोशी देहारी ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किये जा रहे ईवीएम में प्रतिकात्मक रूप से मतदान किया, जिसका अवलोकन व्हीव्हीपेट के माध्यम से किया गया।

जब गांव पहुंचा 7 फीट का मगरमच्छ

कोरबा। पाली के कुछ गांव खुटाघाट जलाशय से लगे हुए हैं। जिससे यहां के लोगों को अक्सर डर डर कर रहना पड़ता है। मंगलवार को भी ऐसा ही कुछ हुआ कि कुछ देर तक लोगों की सांसे थम गई। खुटाघाट जलाशय में बड़ी तादात में मगरमच्छ रहते हैं। जो आए दिन भटककर पाली क्षेत्र के कई गांवों में चले जाते हैं। मंगलवार को भी एक मगरमच्छ शिवपुरी गांव के नजदीक कुंभीपानी जलाशय पहुंच गया। जिसको देख गांव में हल्ला मच गया। पूरे गांव में दहशत फैल गई। तुरंत गांव के लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम गांव पहुंची और मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। वन विभाग अपने कर्मचारियों के साथ गांव पहुंची। रेंजर संजय लकड़ा और डिप्टी रेंजर बाबूलाल उरांव ने दूसरे कर्मचारियों और गांव वालों के साथ मिलकर मगरमच्छ को काबू में किया। मगरमच्छ को पकड़ कर खुटाघाट जलाशय में छोड़ दिया गया। रेस्क्यू करने के लिए वन विभाग की टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। 7 फीट का मगरमच्छ काफी फुर्तीला था।

रायगढ़ लोकसभा चुनाव में खिलेगा कमल या पंजा दिखाएगा जादू

रायगढ़। रायगढ़ लोकसभा सीट छत्तीसगढ़ का अहम सीट माना जाता है। इसका आधा भाग बिलासपुर संभाग और आधा भाग सरगुजा संभाग में पड़ता है। कुल आठ विधानसभा सीटों से मिलकर यह लोकसभा सीट बना है। इसमें जशपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव। लैलूंगा, रायगढ़, सारंगढ़, खरसिया और धरमजयगढ़ शामिल है। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से हमेशा से कांटे की टक्कर रही है। लेकिन 1999 लोकसभा चुनाव से लेकर साल 2019 के लोकसभा चुनाव तक यहां बीजेपी का कब्जा रहा।

1999 से अब तक रायगढ़ सीट पर बीजेपी का रहा कब्जा

1999 के लोकसभा चुनाव से लेकर साल 2019 के लोकसभा चुनाव तक इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। लगातार पांच बार से रायगढ़ लोकसभा सीट पर चुनाव में बीजेपी जीत दर्ज करती आ रही है। इस बार यहां से सांसद गोमती साय ने सांसद पद से इस्तीफा देकर विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने का काम किया। गोमती साय ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में पत्थलगांव सीट से जीत दर्ज की।

साल 2009 से साल 2019 में हुए आम चुनाव के नतीजे

साल 2009 में रायगढ़ संसदीय क्षेत्र में कुल 1432746 मतदाता थे। वैध वोटों की कुल संख्या 935746 थी। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विष्णु देव साय जीते और सांसद बने। उन्हें कुल 443948 वोट हासिल हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार हृदयराम राठिया कुल 388100 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। इसी तरह साल 2014 के लोकसभा चुनाव में

रायगढ़ संसदीय क्षेत्र में कुल 1626949 मतदाता थे। वैध वोटों की कुल संख्या 1217706 थी। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विष्णु देव साय जीते और सांसद बने। उन्हें कुल 662478 वोट मिले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उम्मीदवार आरती सिंह कुल 445728 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहीं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में रायगढ़ संसदीय क्षेत्र में कुल 1733805 मतदाता थे। कुल वैध वोटों की संख्या 1334395 थी। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार गोमती साई जीतकर सांसद बनीं। उन्हें कुल 658335 वोट मिले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार लालजीत सिंह राठिया कुल 592308 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे।

विधानसभावार रायगढ़ लोकसभा सीट पर नजर

साल 2019 के लोकसभा चुनाव में विधानसभावार परिणाम पर अगर गौर करें तो यहां की पांच विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी ने जीत दर्ज की। जबकि तीन विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। जशपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने 57.57 प्रतिशत वोट हासिल किया। कुनकुरी विधानसा सीट पर बीजेपी ने 57.35 प्रतिशत वोट हासिल किया और नंबर एक स्थान पर रही। लैलूंगा विधानसभा एरिया में बीजेपी ने 48.30 प्रतिशत वोट प्राप्त किया। रायगढ़ विधानसभा सीट पर भी बीजेपी ने वोट शेयर में इजाफा किया और यहां 60.76 प्रतिशत वोट हासिल किया। सारंगढ़ में बीजेपी ने 46.81 वोट प्राप्त किया। जबकि कांग्रेस ने पत्थलगांव में 49.16 फीसदी वोट हासिल कर जीत दर्ज की। इसके अलावा कांग्रेस को खरसिया में 53.71 वोट मिले और धरमजयगढ़ में 54।30 फीसदी वोट मिले।

वोट प्रतिशत पर एक नजर

साल 2004 के लोकसभा चुनाव में रायगढ़ में कुल 62.43 फीसदी वोटिंग हुई। साल 2009 के संसदीय चुनाव में कुल 65.31 फीसदी वोटिंग हुई। जबकि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में 76.6 फीसदी मतदान हुआ। इसी तरह साल 2019 में कुल 77.87 प्रतिशत वोटिंग हुई।

गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से 9 अग्निवीर युवाओं का चयन

गौरेला पेंड्रा मरवाही। भारतीय थल सेना (अग्निवीर) में छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित करने वाले 870 युवाओ का चयन किया गया है। इनमें गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले से 9 अग्निवीर युवा शामिल हैं। सभी चयनित अग्निवीर युवाओ का सम्मान समारोह 14 मार्च गुरूवार को सुबह 9 बजे राजधानी रायपुर के शहीद स्मारक भवन में आयोजित किया गया है। इस सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री एवं गृह, जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा, रोजगार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री विजय शर्मा होंगे। जीपीएम जिले से चयनित अग्निवीर युवाओं-अभिषेक, बादल पुरी, दीपक कुमार, लक्ष्मण बघोव, कमलेश राठौर, वीरेन्द्र राठौर, रवि कुमार, पंकज राठौर एवं मनोज सिंह को सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए जिला प्रशासन की ओर से समुचित व्यवस्था की गई है। अपर कलेक्टर श्रीमती नम्रता आनंद डोगरे ने बधाई एवं शुभकामनाओ के साथ युवाओं के वाहन को आज हरी झण्डी दिखाकर कलेक्ट्रेट परिसर से रायपुर के लिए रवाना किया।

संक्षिप्त समाचार

यूपीएससी की तर्ज पर होगी सीजीपीएससी की परीक्षाएं

रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को संघ लोक सेवा अयोग की तर्ज पर पारदर्शी बनाने के लिए सुझाव देने के लिए संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. प्रदीप कुमार जोशी की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया है। इस संबंध में महानदी भवन मंत्रालय स्थित सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. प्रदीप कुमार जोशी की अध्यक्षता में गठित आयोग छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं को संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर पारदर्शी बनाने हेतु सुझाव देने के साथ ही विभिन्न विभागों के लिए परीक्षा आयोजन का वार्षिक कैलेण्डर बनाने तथा परीक्षार्थियों में आयोग के प्रति विश्वसनीयता बनाए जाने के लिए भी सुझाव देगी।

अवैध शराब मामले में रिश्वत लेना पड़ा महंगा, एएसआई सस्पेंड

कोरबा। अवैध शराब के प्रकरण में रिश्वत लेने के मामले में एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने एक्शन लेते हुए बांगो थाना में पदस्थ एएसआई को सस्पेंड कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। बता दें कि कुछ लोगों ने एएसआई पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया था। एएसआई सुखलाल सिदार के खिलाफ स्थानीय ग्रामीणों ने लिखित शिकायत भी की थी। मामले की जांच में सत्यता पाए जाने पर एसपी ने तत्काल एक्शन लेते हुए एएसआई सुखलाल सिदार को सस्पेंड कर दिया है। एसपी की इस कार्रवाई के बाद पुलिस कर्मियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है।

श्रीमंत झा ने इटली पैरा आर्म्रेसलिंग चैम्पियनशिप में जीता सिल्वर

रायपुर। छत्तीसगढ़ के श्रीमंत झा ने एक बार फिर भिलाई सहित छत्तीसगढ़ का नाम पूरे देश में रोशन किया। इटली में आयोजित इटली पैरा आर्म्रेसलिंग चैंपियनशिप में श्रीमंत झा ने सिल्वर मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है, जीते हुए पदक को देश के शहीद जवानों के नाम समर्पित किया है.श्रीमंत झा एशिया के एकमात्र और विश्व के तीसरे नंबर के पैरा आर्म रेसलिंग खिलाड़ी है। 8 से 10 मार्च के बीच इटली में इटली पैरा आर्म्रेसलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें एशिया के पहले और भारत के तरफ से श्रीमंत झा थे. श्रीमंत झा ने पीआईयूएच वर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हुए झा ने क्वार्टर फाइनल में इटली खिलाड़ी बोजो बोगुनोविक को हराया और सेमीफाइनल में उन्होंने यूक्रेन के खिलाड़ी माटेओ पेट्रोविक को एक प्रभावशाली मुकाबले में हराया। विक्टर ब्रैचेनिया ने श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता. श्रीमंत झा ने अपने जीते हुए पदक को देश के लिए शहीद जवानों के नाम समर्पित किया है। श्रीमंत झा ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय जिंदल स्टील एंड पावर के अध्यक्ष नवीन जिंदल, पीपुल्स आर्म रेसलिंग फेडरेशन इंडिया की अध्यक्ष प्रीति झंगियानी और महासचिव लक्ष्मण सिंह भंडारी और चेयरमैन सुरेश बेब को दिया है। श्रीमंत झा ने कहा कि कोच और फिटनेस कोच ऋषभ जैन और राजू साहू ने दो महीने पहले छत्तीसगढ़ में जो काम किया, उससे मुझे यह पदक पाने में मदद मिली।

आईपीएस अधिकारी राहुल भगत को मिला सुशासन और अभिसरण विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार

रायपुर। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में अधिकारियों का प्रमोशन, ट्रांसफर का सिलसिला जारी है। लगातार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला किया जा रहा है। इसी क्रम में राज्य शासन ने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी राहुल भगत को एक और जिम्मेदारी दी है। राहुल भगत को सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। इसके लिए राज्य शासन ने आदेश जारी किया है।

मुख्यमंत्री से रामनामी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने की सौजन्य मुलाकात

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से यहां

उनके निवास परिसर में छत्तीसगढ़ रामनामी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने श्री रामलला दर्शन योजना की शुरुआत के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का हार्दिक आभार जताया। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री साय से कहा कि अयोध्याधाम में प्रभु श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने से छत्तीसगढ़ के सभी लोगों में अपार हर्ष है। छत्तीसगढ़ माता शबरी की भूमि है। यहां के कण-कण में प्रभु श्री राम व्याप्त हैं। राज्य सरकार द्वारा सरकारी खर्च पर छत्तीसगढ़ के लोगों को अयोध्याधाम की यात्रा कराई जा रही है। इस योजना से प्रभु श्री राम के ननिहाल के लोगों को श्री आयोध्या धाम के दर्शन का अनुपम अवसर मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि अयोध्याधाम के लिए श्रद्धालुओं को लेकर विशेष ट्रेन रवाना हो रही है। एक बार में लगभग 850 दर्शनार्थी प्रभु श्री रामलला के दर्शन को आयोध्या जा रहे हैं। इस यात्रा में श्रद्धालुओं के ठहरने, भोजन सहित सभी सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। हमारी सरकार छत्तीसगढ़ के सभी श्रद्धालुओं को प्रभु श्री रामलला के दर्शन पूरे शासकीय खर्च पर करवाएगी।

साय सरकार के तीन माह हुए पूरे 20 में 14 गारंटी किया पूरा

13 दिसंबर को भाजपा सरकार ने किया था शपथ ग्रहण

रायपुर। भाजपा सरकार के कार्यकाल को आज तीन महीने पूरे हो रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद 13 दिसंबर को विष्णुदेव साय सरकार ने शपथ ली थी। शपथ के बाद से ही प्रदेश में गारंटियों के पूरा होने का सिलसिला शुरू हो गया। भाजपा ने 20 में से 14 गारंटियों को लोकसभा चुनाव के पहले ही पूरा कर दिया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण महतारी वंदन योजना, 3100 रुपये में धान खरीदी, 18 लाख पीएम आवास,रामलला मंदिर दर्शन योजना लागू हो चुकी है, वहीं पीएससी परीक्षा घोटाले में सीबीआई जांच की अनुशंसा प्रमुख रूप से शामिल हैं।

इसके अलावा भाजपा ने 1,000 किमी लंबी शक्तिपीठ परियोजना, रामलला मंदिर दर्शन योजना, तेंदूपत्ता संग्राहकों को 5500 रुपये, बिरनपुर सीबीआई जांच, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को हर वर्ष 10 हजार रुपये की

सहायता,दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन, दो साल धान का बकाया बोनस, पांच सालों तक गरीब परिवारों को फ्री में चावल, पत्ता संग्राहकों को 4500 रुपये बोनस पर भी मुहर लगा दी है। भाजपा पदाधिकारियों के मुताबिक सरकार ने 100 दिनों की कार्ययोजना बनाकर जिम्मेदारी बांट दी है। इसी आधार पर मंत्रिमंडल ने भी योजनाओं को पूरा करने की रणनीति बनाई है।

रसोई गैस सब्सिडी का इंतजार- गारंटियों में अभी भी रसोई गैस में 500 रुपये की छूट का इंतजार महिलाओं को हैं। छात्रों के लिए मासिक ट्रैवल अलाउंस, भ्रष्टाचार के खिलाफ आयोग का गठन का वादा पूरा होना बाकी है। भाजपा सूत्रों के मुताबिक रसोई गैस को लेकर एलपीजी कंपनियों से चर्चा जारी है। शीघ्र ही इस गारंटी पर भी मुहर लगेगी।

किसानों को सबसे ज्यादा फायदा- राज्य में भाजपा सरकार ने अपनी गारंटियों में किसानों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा है। 24.72 लाख किसानों के खाते में 12 मार्च को धान खरीदी की अंतर की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी गई। सरकार ने इसके लिए 13320 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। इससे पहले किसानों को दो वर्ष के धान के बोनस के रूप में 3716 करोड़ रुपये व धान खरीदी के एवज में 30 हजार 68 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

युवाओं को भी साधा- राज्य सरकार ने पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच की अनुशंसा करने के साथ ही शिक्षक व पुलिस भर्ती प्रक्रिया शुरू करते हुए युवाओं को साधने का प्रयास किया है। भाजपा ने अपने घोषणा-पत्र में सरकारी विभागों में भर्तियों का वादा किया है। इस वादे को भी पूरा करने की कवायद शुरू हो चुकी है।

महतारी वंदन योजना- महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की 68.53 लाख महिलाओं के खातों में 636.44 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार योजना की शेष महिला हितग्राहियों के खातों में राशि का अंतरण प्रक्रियाधीन है। महतारी वंदन योजना के तहत एक-एक हजार रुपये डीबीटी के माध्यम से प्रतिमाह के मान से साल में 12 हजार रुपये महिला हितग्राहियों के बैंक खातों में अंतरित किए जाएंगे।

86 कार्यों की स्वीकृति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र

रायपुर। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव द्वारा मुंगेली जिले के लोरमी विकासखंड के विभिन्न गांवों में मुख्यमंत्री अधोसंरचना संधारण एवं उन्नयन प्राधिकरण से निर्माण एवं मरम्मत कार्यों के भेजे प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय ने सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री सचिवालय ने सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखकर उप मुख्यमंत्री द्वारा अनुशंसित कार्यों के लिए राशि जारी करने का आग्रह किया है। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने लोरमी विकासखंड के विभिन्न गांवों में तीन करोड़ तीन लाख रुपए लागत के 86 कार्यों की स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री अधोसंरचना संधारण एवं उन्नयन प्राधिकरण को प्रस्ताव भेजा है।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने लोरमी विकासखंड में 45 लाख रुपए की लागत के 44 आंगनबाड़ी केंद्रों के मरम्मत एवं उन्नयन कार्य, एक करोड़ 60 लाख रुपए लागत के 23 स्कूलों में अतिरिक्त कमरा निर्माण, शौचालय निर्माण, किचन शेड, मरम्मत कार्य एवं पेयजल व्यवस्था तथा 58 लाख रुपए लागत के नौ सीसी रोड व अहाता निर्माण का प्रस्ताव मुख्यमंत्री अधोसंरचना संधारण एवं उन्नयन प्राधिकरण को प्रस्ताव भेजा है। उन्होंने आठ लाख रुपए की लागत से दो उप स्वास्थ्य केंद्रों के मरम्मत, संधारण एवं उन्नयन कार्य, छह लाख रुपए की लागत से दो उप स्वास्थ्य केंद्रों में बाउंड्रीवॉल निर्माण, सात लाख रुपए की लागत से एक उप स्वास्थ्य केंद्र में मुख्य मार्ग से अस्पताल तक सीसी रोड निर्माण, 16 लाख रुपए लागत के चार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बाउंड्रीवॉल निर्माण और लोरमी के 50 बिस्तर अस्पताल में जेनरेटर के लिए तीन लाख रुपए का प्रस्ताव भी प्राधिकरण को अनुशंसित किया है।

ईडी की ओर से पेश पूरक चालान के बाद आज सुनवाई

रायपुर। महादेव एप सट्टेबाजी मामले में ईडी ने विशेष कोर्ट में नितिन टिबरेवाल, अमित अग्रवाल और नीतिश दीवान की भूमिका पर 3500 पन्नों का पूरक अभियोजन परिवाद पेश किया है। ईडी की ओर से पेश किए गए पूरक चालान में महादेव एप बुक के संचालन में नितिन टिबरेवाल, अमित अग्रवाल और नीतिश दीवान की अहम भूमिका होने का उल्लेख करते हुए हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव आदि कोर्ट में जमा कराया है। चालान में नीतिश दीवान को महादेव एप के संचालकों के साथ नजदीकी संबंध, एप के संचालन में मैनेजर के रूप में दी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन के साथ ही कोर कमेटी का सदस्य भी बताया गया है।

ईडी का दावा है कि नितिन टिबरेवाल ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के जरिए सट्टेबाजी का करोड़ों रुपये निवेश किया है। वहीं अमित अग्रवाल पर महादेव एप की कमाई से मिलने वाली नकदी रकम को अनेक बैंक खातों में लेकर निवेश कराया है। उसके द्वारा काली कमाई से छेरीखेड़ी में जमीने खरीदने के भी ठोस दस्तावेज व सबूत मिले है। मामले की सुनवाई 14 मार्च को होगी।

गौरतलब है कि महादेव एप सट्टेबाजी मामले में ईडी की गिरफ्त में आए भोपाल के मुख्य ऑपरेटर गिरीश तलरेजा और कोलकाता निवासी सूरज चोखानी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल में भेज दिया गया है। वहीं ईडी के प्रतिवेदन पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने अज्ञात पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ साजिश, जालसाजी और भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया है।

राज्य खेल अलंकरण समारोह, मुख्यमंत्री आज राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को करेंगे पुरस्कृत

■ **अलंकरण समारोह प. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में प्रातः 11 बजे से**

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय 14 मार्च को राज्य खेल अलंकरण समारोह में राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को पुरस्कृत करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह करेंगे। कार्यक्रम के अतिविशिष्ट अतिथि उपमुख्यमंत्री द्वय श्री अरूण साव और श्री विजय शर्मा तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री टंकराम वर्मा होंगे। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा राज्य खेल अलंकरण समारोह का आयोजन पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में प्रातः 11 बजे से किया जाएगा।

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, वन मंत्री श्री केदार कश्यप, खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल, वित्त

मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, विधायक सर्व श्री राजेश मूणत, पुरन्दर मिश्रा, मोतीलाल साहू, अनुज शर्मा, इन्द्रकुमार साहू, गुरू खुशवंत साहेब होंगे।

कार्यक्रम में राज्य शासन द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार के लिए 06, शहीद कौशल यादव पुरस्कार के लिए 06, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार के लिए 02, शहीद पंकज विक्रम सम्मान 27, शहीद विनोद चौबे सम्मान के लिए 05 एवं मुख्यमंत्री ट्राफी के लिए 25 खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। इसी प्रकार वर्ष 2020-21 हेतु शहीद राजीव पांडेय पुरस्कार के लिए 11, शहीद कौशल यादव पुरस्कार के लिए 03, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार के लिए 01, शहीद पंकज विक्रम सम्मान 16, शहीद विनोद चौबे सम्मान के लिए 05 एवं मुख्यमंत्री ट्राफी के लिए 26 चयनित खिलाड़ियों को ट्राफी देकर सम्मानित किया जाएगा।

कार्यक्रम में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त खिलाड़ियों को अलंकरण से सम्मानित करते हुए 269 खिलाड़ियों को वर्ष 2019-20 के लिए पुरस्कार राशि 30.36 लाख रूपए तथा 2020-21 के लिए 142 खिलाड़ियों को 19 लाख 32 हजार रूपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी।

छत्तीसगढ़ में 41 से अधिक जजों का तबादला

बिलासपुर। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने हायर ज्यूडशियल सर्विस के 41 से अधिक जजों का तबादला आदेश के साथ ही लॉ ऑफिसर्स के प्रभार में बदलाव भी किया है। जारी आदेश के मुताबिक, उच्च न्यायिक सेवा के अफसर बलराम प्रसाद वर्मा को रजिस्ट्रार विजिलेंस की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

वहीं, दुर्ग के परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश सिराजुद्दीन कुरैशी को हाईकोर्ट की स्थापना शाखा में छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी बिलासपुर के निदेशक के रूप में स्थानांतरित कर पदस्थापना दी गई है।

जारी आदेश के तहत रजिस्ट्रार (आई एंड ई) बलराम प्रसाद वर्मा को हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार (सतर्कता) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। राजनांदगांव के जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार को हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार (आइ एंड ई) की जिम्मेदारी दी गई है। दुर्ग के चतुर्थ अतिरिक्त सत्र एवं जिला सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार वर्मा को हाईकोर्ट के स्थापना शाखा में अतिरिक्त रजिस्ट्रार के पद पर पदस्थ किया गया

है।

कोरबा जिले के कटघोरा में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश वेन्सेस्लास टोप्पो को हाईकोर्ट के स्थापना शाखा में रजिस्ट्रार (कम्प्यूटरीकरण) के पद पर तबादला किया गया है। मनेंद्रगढ़ के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी कोर्ट के आनंद प्रकाश दीक्षित का भी हाईकोर्ट के स्थापना शाखा और राज्य न्यायिक अकादमी में अतिरिक्त निदेशक बनाया गया है।

हाईकोर्ट ने हायर ज्यूडिशियल सर्विस के चार एडिशनल सेशन जजों को स्पेशल जज के रूप में पदस्थ कर ट्रांसफर किया है। इसमें दुर्ग के एडिशनल सेशन जज संजीव कुमार टामक को दुर्ग, रायपुर के कमर्शियल कोर्ट के जज जयदीप गर्ग को कोरबा, बेमेतरा के एडिशनल सेशन जज पंकज कुमार सिन्हा को रायपुर, अंबिकापुर के एडिशनल सेशन जज मनोज कुमार सिंह को अंबिकापुर में ही पदस्थ किया गया है।

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने हायर ज्यूडिसियल सर्विस के 34 जजों का ट्रांसफर आदेश भी जारी किया है। इसके तहत दुर्ग, रायपुर, कोरबा, जगदलपुर, भाटापारा सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों के लोअर कोर्ट में पदस्थ एडिशनल सेशन जज शामिल हैं।

हाईकोर्ट ने 40 से अधिक न्यायिक अधिकारियों के तबादले भी किए हैं। बलराम प्रसाद वर्मा को हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार विजिलेंस नियुक्त किया गया है। अब तक वे प्रभार संभाल रहे थे। वहीं, ज्यूडिशियल एकेडमी की डायरेक्टर सुषमा सावंत राजनांदगांव की जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाई गई हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव आनंद प्रकाश वारियल को सूरजपुर में एडीजे बनाया गया है।

पर्यटन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सरकार को मिला आवार्ड

रायपुर। वर्ल्ड ट्रैवल और टूरिज्म काउंसिल इंडिया इनिशिएटिव ने पर्यटन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को अवार्ड दिया है। यह अवार्ड नई दिल्ली के होटल ललित में जी 20 शेरपा अमिताभ कांत और केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय की महानिदेशक मनीषा सक्सेना ने प्रदान किया। छत्तीसगढ़ के संस्कृति, पर्यटन और शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के प्रतिनिधि के रूप में उनके विशेष कार्य अधिकारी अतुल सिंघल ने यह अवार्ड ग्रहण किया। मंत्री अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अब डबल इंजन की सरकार है और पिछले पांच साल के दौरान विकास की गति को ब्रेक लग गया था, लेकिन उसे फिर से विकास के पंख लग गए हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, जिनका सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ क्रियान्वयन कर रही है।

14000 से ज्यादा परिवारों को मिलेगा घरेलू नल कनेक्शन: ईश्वर

■ **विधायक ने किया ग्राम खम्हरिया समूह जल प्रदाय योजना का भूमि पूजन**

बेमेतरा। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन योजना गर्त विधायक साजा श्री ईश्वर साहू ने बीते मंगलवार को बेमेतरा जिले के विकासखंड साजा के ग्राम खम्हरिया में समूह जल प्रदाय योजना का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य (सभापति बेमेतरा) श्री गोवेन्द्र पटेल श्री ज्वाला ठाकुर, श्री बल्लू साहू, श्री स्वरूपानंद साहू पूर्व सरपंच ग्राम खम्हरिया सीताराम साहू पंच, सुकल साहू पंच, व्यास साहू पंच, पूर्णानंद साहू, परमेश्वर साहू आदि उपस्थिति थे। अतिथियों का स्वागत कार्यपालन अभियंता,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री आर.के धनंजय ने किया।

विधायक ईश्वर साहू नए कहा कि इससे क्षेत्र के 62 ग्रामों को शिवनाथ नदी से प्राप्त जल को शुद्धिकरण संयंत्र द्वारा मीठा जल प्रदाय किया जाएगा। जिनमें लगभग 14356 परिवारों को घरेलू जल कनेक्शन के माध्यम से (स्वच्छ) मीठा जल प्रदाय होगा। परिवारों के लगभग 74690 की सदस्य लाभान्वित हो होंगे।

कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री आर.के धनंजय ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत इस पर लगभग 70 करोड़ खर्च होंगे। इस योजना के मुख्य घटकों में 6.5 एम.एल.डी. (65 लाख लीटर) आवक क्षमता का जल शुद्धिकरण संयंत्र का निर्माण किया जाएगा एवं 6 मी. व्यास का इंटेकवेल स्ट्रक्चर निर्माण, 4 नग आर.सी.सी. एम.बी.आर. (उच्चस्तरीय जलागार) निर्माण, क्लियर वाटर पंपिंग मेन (लगभग 51 कि.मी.) विभिन्न व्यास के लगभग 148 कि.मी. पाईप लाईन विस्तार तथा अन्य कार्य लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा किया जावेगा।

मनरेगा कर्मचारी महासंघ ने साव को याद दिलाया वादा

■ **कहा- 3 माह से वेतन नहीं, दीगर काम लेकर नौकरी से निकाला जा रहा**

रायपुर। छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय पदाधिकारी सहित मुंगेली की टीम ने डिप्टी सीएम अरुण साव से मुलाकात कर अपनी मांगों एवं विधानसभा चुनाव में किए गए नियमितिकरण के वादे को याद दिलाते हुए ज्ञापन सौंपा। उप मुख्यमंत्री साव ने पूर्व सरकार के दौरान मनरेगा कर्मियों के संघर्ष को याद किया।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ बीजेपी किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष, लोरमी के पूर्व विधायक व वर्तमान में बिलासपुर लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी तोखन साहू जी ने मनरेगा कर्मियों की मांगो का समर्थन करते हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी की

जीत में मनरेगा कर्मियों के अहम योगदान को बताते हुए उप मुख्यमंत्री को उनकी मांगों को पूरा करने के लिए समर्थन किया।

प्रांताध्यक्ष अजय क्षत्री ने लोकसभा चुनाव पूर्व राजस्थान में हुए नियमितीकरण अनुसार छत्तीसगढ़ में भी मनरेगा कर्मियों के नियमितिकरण किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा, जिस प्रकार पूर्व में भाजपा की सरकार में संविदा शिक्षकों (शिक्षाकर्मी), क्रेडा विभाग के कर्मचारी एवं विभिन्न विभागों के संविदा/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारीगण को नियमित किया गया है उसी प्रकार मनरेगा कर्मियों को भी नियमित किया जाए।

डिप्टी सीएम को अवगत कराया गया कि मनरेगा कर्मियों से भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार महात्मा गांधी नरेगा के अलावा अन्य योजनाओं/विभागों का कार्य नहीं लेना चाहिए, किंतु जिलों में दूसरे विभागों या योजनाओं के कार्यों को लक्षित करते हुए किसी भी मनरेगा कर्मी पर द्वेष पूर्ण अथवा सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार की कारवाई को तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए। साथ ही वर्तमान में कई मनरेगा कर्मी के विरुद्ध जिला, जनपद स्तर पर किए गए पत्राचार एवं कार्रवाई को तत्काल शून्य किया जाए।

माह जनवरी 2024 से वेतन भुगतान प्राप्त नहीं होने, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने व पैसों की तंगी के कारण पारिवारिक हालत खराब होने का हवाला देते हुए समस्त तकनीकी सहायक, बीएफटी, रोजगार सहायक व अन्य मनरेगा कर्मियों के रोके गये वेतन/मानदेय का होली महापर्व के पूर्व भुगतान कराने की मांग भी की गई। इस दौरान छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय क्षत्री, नितिन चंद्राकर, महेश डाहीरे, इम्तियाज अली, योगेश सोनी, भूपेंद्र देवांगन, पैकरा, मनीष सहित मुंगेली जिले के अन्य मनरेगा कर्मी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जगदलपुर जिला-बस्तर (छ.ग.)
दूरभाष क्र. 07782-222336 (कार्या.) फैक्स नं. 225777 ई-मेल spofficejdr@gmail.com

// हाउसकीपिंग (साफ-सफाई) कार्य निविदा आमंत्रण सूचना// द्वितीय बार

क्रमांक पु.अ./बस्तर/रा.नि./रीडर/777-डी/2024, दिनांक 09/03/2024

पुलिस विभाग जिला बस्तर अंतर्गत आने वाले कार्यालय भवनों की हाउसकीपिंग (साफ-सफाई) कार्य हेतु वार्षिक अनुबंध के लिए इच्छुक संस्था/फर्म जिन्हें किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय / नगरीय निकायों / सार्वजनिक उपक्रमों में कार्य करने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो, ठेका दिये जाने हेतु दिनांक 21/03/2024 को 15.00 बजे अपरान्ह तक सीलबंध लिफाफे में निविदा / भावपत्र आमंत्रित किये जाते हैं, प्राप्त निविदाएं उसी दिन सायं 16.00 बजे उपस्थित निविदाकारों (यदि उपस्थित रहना चाहते हैं) के समक्ष खोली जाएगी। निविदा प्रपत्र क्रय हेतु कार्यालयीन समय में (अवकाश के दिनों को छोड़कर) 500/- (पांच सौ रूपये) का चालान लेखा शीर्ष 0055 पुलिस शीर्ष 800 अन्य प्राप्तियां मद में जमा कर चालान की मूल प्रति रक्षित निरीक्षक, कार्यालय जगदलपुर में दिनांक 11-03-24 से प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकता है ।

1. निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि- 19-03-2024 को सांय 17.00 बजे तक
2. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि- 21-03-2024 को सायं 15.00 बजे तक
3. निविदा खोलने की तिथि- 21-03-2024 को सायं 16.00 बजे तक

पुलिस अधीक्षक
बस्तर, जगदलपुर
जी- 08470/5

इंडिया गठबन्धन की उलझनों से भाजपा की राह आसान

ललित गर्ग

इंडिया गठबन्धन लगातार कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है जबकि केंद्र की सत्ता पर काबिज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन-एनडीए में नये दलों के जुड़ने की खबरों से उसके बड़े लक्ष्य के साथ जीत की राह आसान होती जा रही है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दलों के साथ 400 सीटें जीतने का लक्ष्य निश्चित किया है। भाजपा जहां इस बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पुराने सहयोगियों को फिर से साध रही है तो दूसरे दलों के नेताओं को अपने पाले में करने पर भी पार्टी का जोर है और वह इसमें बड़ी सफलताओं को प्राप्त कर रही है। ओडिशा में बीजेडी और आंध्र में टीडीपी से गठबंधन पक्का माना जा रहा है। त्रिपुरा का मुख्य विपक्षी दल टिपरा मोथा भी अब भाजपा सरकार में शामिल हो गया है। भाजपा पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक चुनावी समीकरण सेट करने एवं विभिन्न दलों को एनडीए में शामिल करने की रणनीति में जुटी है। भाजपा ने अभी अनेक प्रांतों में अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है, ताकि दूसरे दलों के एनडीए में शामिल करने एवं उनसे सीटों के समीकरण को सेट करने के दरवाजे खुले रहे। निश्चित रूप से भाजपा की यह मजबूत होती स्थिति विपक्ष की एकता के लिए अच्छी खबर नहीं कही जा सकती क्योंकि इंडिया गठबन्धन विभिन्न मजबूत क्षेत्रीय दलों का ही गठबन्धन माना जाता है जिसमें कांग्रेस एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है। समाजवादी पार्टी एवं आम आदमी पार्टी के अलावा अन्य क्षेत्रीय दलों में उतना दम नहीं है, या अनेक मजबूत दल एनडीए के साथ जुड़ चुके हैं या उन्होंने स्वतंत्र चुनाव लड़ने की घोषणा करके इंडिया गठबन्धन की सांसें छीन ली है। इन नये गठजोड़ों से बनते राजनीतिक परिदृश्य इंडिया गठबन्धन के लिये चिन्ता का कारण है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक होंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन में क्षेत्रीय दलों को जोड़ा जा रहा है, तो दूसरी तरफ खड़ा है इंडिया गठबंधन। कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने भी कुछ राज्यों में अपने सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग पर बात बना ली है। कुछ पर अब भी बात चल रही है। भाजपा ने 2 मार्च को अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नाम थे। कुछ ऐसे राज्य बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, हरियाणा, पंजाब और कर्नाटक हैं जहां से भाजपा ने एक भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की। इन राज्यों के एक भी सीट पर उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं करने का कारण है- भाजपा की अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन या गठबंधन के दलों के साथ सीट शेयरिंग पर अब भी चल रही बातचीत में संभावनाएं तलाशने की रणनीति। लोकसभा चुनाव सन्निकट हैं। इंडिया गठबन्धन एवं एनडीए रूठे नेताओं को मनाने, गठबंधन का गणित सेट करने और पुराने सहयोगियों को फिर से साथ लाकर कुनबा बढ़ाने की कोशिशों में जुटे हैं। भाजपा ने इन चुनावों में 'अबकी पार, 400 पार' का नारा दिया है। अब पार्टी इस नारे को चुनाव नतीजे में तब्दील करने के लिए व्यापक स्तर पर गठबंधनों की संभावनाओं को तलाश रही है। ओडिशा में बीजू जनता दल और भाजपा का गठबंधन पक्का माना जा रहा है। अगर ये गठबंधन होता है तो राज्य में दोनों ही दलों को बढ़िया चुनाव परिणाम मिल सकते हैं। पटनायक राजनीति के महारथी हैं, उनको भाजपा के साथ गठबंधन करना ही पार्टी एवं राज्य की जनता के हित में प्रतीत हो रहा है। ओडिशा की ही तर्ज पर बिहार में भी नीतीश को मोदी के नेतृत्व में हित दिखाई दिया है। यही कारण है लोकसभा चुनाव के पहले बिहार में राजनीतिक बदलाव करते हुए नीतीश एनडीए से जुड़ गये। इस बदलाव से राज्य में भाजपा और नीतीश कुमार को इस चुनाव में बड़ा फायदा होने की संभावनाएं है। महाराष्ट्र की 48 सीटों में से करीब 32 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ सकती है, वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना को लगभग 12 सीट और अजित पवार की एनसीपी को लगभग 4 सीटें मिल सकती हैं। उधर आंध्र प्रदेश में भाजपा और तेलुगु देशम पार्टी का गठबंधन हो सकता है।

तुष्टिकरण का भ्रम और सीएए

उमेश चतुर्वेदी

2024 के आम चुनावों की घोषणा अभी बाकी है लेकिन चुनावी बयार बहने लगी है। ऐसे में नागरिकता संशोधन कानून, जिसे हम संक्षेप में सीएए के नाम से जानते हैं, लागू किया गया है तो उसे राजनीतिक चश्मे से ही देखा जाएगा। यूं तो सियासी आइने में इस कानून को तभी से देखा जा रहा है, जब से इसे संसद ने पारित किया है। इस कानून को लागू किए जाने को लेकर दो तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। विभाजन की वजह से सीमा के दूसरी ओर से आए लोग हों या अफगानिस्तान या म्यांमार से आए लोग, उनकी प्रसन्नता का पारावार नहीं हैं। उन्हें लगता है कि नागरिकता हासिल करने की उनकी दशकों पुरानी मांग अब पूरी हो जाएगी।

नागरिकता मिलने के बाद वे भी भारत भूमि पर दूसरे लोगों की तरह आधिकारिक तौर पर शिक्षा हासिल कर पाएंगे, जमीन-जायदाद बना पाएंगे, नौकरियां कर पाएंगे और पहले की तुलना में बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। दूसरी तरफ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं। जो अपनी-अपनी राजनीतिक लाइन के हिसाब से हैं। चूंकि इस कानून की पैरोकारी करने वाली अकेली पार्टी बीजेपी है, ऐसे में इस कानून के लागू किए जाने से उसका खुश होना स्वाभाविक है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल और स्वयंसेवी संगठन हैं। जाहिर है कि वे इस कानून के लागू किए जाने को दो तरह से देख रहे हैं। वे जहां इसे पहले की तरह अल्पसंख्यक विरोधी बता रहे हैं, वहीं इसे राजनीतिक दांव भी बता रहे हैं।

इस कानून के लागू होने के बाद पश्चिम बंगाल का मतुआ समुदाय बेहद खुश है। खुश तो राजस्थान के सीमावर्ती शहरों मसलन बाड़मेर, जोधपुर आदि में बसे सीमा पार से आए हिंदू समुदाय के लोग भी हैं। मतुआ समुदाय तो अपनी लड़ाई के बाद कुछ अधिकार हासिल कर चुका है। लेकिन राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में दशकों से रह रहे हिंदू समुदाय के लोग नारकीय जीवन जीने के लिए अब भी मजबूर हैं। वे सरकारी और स्वयंसेवी संस्थाओं से मिले सहयोग के सहारे जी रहे हैं। मतुआ समुदाय प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल के उत्तर चौबीस परगना और दक्षिण चौबीस परगना जिलों में फैला हुआ है। यह समुदाय बांग्लादेश से आया था। दशकों से उनकी मांग स्थायी नागरिकता की रही है। ऐसा माना जा रहा है कि सीएए लागू होने के बाद पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय का जहां थोक समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, वहीं अवैध बांग्लादेशियों से परेशान लोगों का भी साथ मिलेगा। शायद यही वजह है कि ममता बनर्जी बार-बार कह रही हैं कि वे पश्चिम बंगाल में सीएए को लागू नहीं होने देंगी। हालांकि संसद के पारित कानून को लागू न करने देना अवैधानिक ही माना जाएगा।

ममता बनर्जी ने संविधान की शपथ ली है। संसद द्वारा पारित कानून भी संवैधानिकता के ही दायरे में आता है। इसलिए अगर ममता इसे लागू करने से इनकार करती हैं तो एक तरह से वह संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। वैसे आज की राजनीति में अपने निजी राजनीतिक फायदे के लिए अगर राजनीति को संविधान का उल्लंघन करना पड़े, संवैधानिक दायित्वों को किनारे रखना पड़े, या झूठा आश्वासन भी देना पड़े तो राजनीति इससे चूकती नहीं। सीएए ना लागू करने के ममता के दावों को भी राजनीति के इसी नए पाठ के दायरे में देखा-परखा जा सकता है। सीएए का मकसद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और बर्मा से आए धार्मिक अल्पसंख्यकों हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता देने की व्यवस्था करता है। 11 दिसंबर 2019 को जब इस कानून को संसद ने पारित किया तो भारत के अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय को कुछ राजनीतिक दलों और स्वयंसेवी संगठनों ने भड़काया था। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों को समझाया कि इस कानून को लागू किए जाने के बाद वे भारत में दूसरे दर्जे के नागरिक बन जाएंगे।

स्वाधीनता के बाद से ही अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों की समूची मानसिकता राजनीतिक दलों और उनके संरक्षक बनने का दावा करने वाले स्वयंसेवी संगठनों के ही समझ के अनुसार चलती रही है। सीएए के खिलाफ उठे देशव्यापी विवाद को भी इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। हालांकि भारत सरकार ने बार-बार इससे इनकार किया है कि यह कानून मुसलमानों के खिलाफ है। चूंकि मुस्लिम समुदाय में भाजपा को लेकर भरोसा नहीं है, लिहाजा उसने भाजपा के संदेशों की बजाय विपक्षी दलों के दावों पर ज्यादा भरोसा किया। विपक्षी दलों को लगता है कि सीएए के लागू होने का बीजेपी को सीधा फायदा पश्चिम बंगाल की बजाय असम में भी मिलेगा। जहां राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी बड़ा मुद्दा है। असम में 1985 में अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों को मुद्दे को लेकर हुए आंदोलन के बाद भारत सरकार के साथ एक समझौता हुआ था। जिसके मुताबिक, 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से असम आए अप्रवासियों की पहचान की जानी थी और उन्हें बाहर करना था। राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर इसीलिए असम में ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है।

असम के कई जिलों में बांग्लादेशी अप्रवासियों की वजह से जनसांख्यिकी गड़बड़ हो गई है। यह मसला वहां एक तरह जहां बहुसंख्यकों को चिंतित करता है, वहीं अल्पसंख्यकों यानी मुस्लिम समुदाय को भी परेशान करता है। बहुसंख्यकों को लगता है कि अवैध अप्रवासियों के चलते उनके अधिकार छीन रहे हैं। जबकि अल्पसंख्यकों को लगता है कि एनआरसी और सीएए के लागू होने के बाद उन्हें असम छोड़ना पड़ सकता है। यही वजह है कि माना जा रहा है कि सीएए के लागू होने के बाद असम में भी अल्पसंख्यक- बहुसंख्यक गोलबंदी होगी। जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। शायद यही वजह है कि असम के कांग्रेसी विधायक अखिल गोगोई इसके विरोध में उतर आए हैं।

रही बात राजनीति की, तो आज राजनीति कौन नहीं कर रहा? अल्पसंख्यक यानी मुस्लिमों के नाम पर अब तक राजनीति करने वाले कांग्रेस और वामपंथी दलों को पहली बार उनकी ही भाषा में जवाब मिल रहा है। चूंकि आज की पूरी राजनीति चुनाव केंद्रित है और सत्ताओं के बिना राजनीतिक उद्देश्य भी हासिल नहीं किए जा सकते, इसलिए राजनीतिक ताकतें साध्य सत्ता के लिए मुफीद राजनीतिक कदमों को अपना साधन बनाती हैं। भाजपा भी अगर ऐसा कर रही है तो उसके समर्थक इसे अतीत की ऐसी राजनीति के जवाब के तौर पर देख रहे हैं। जब कानून पारित हुआ था, तब शायद सरकार को व्यापक विरोध की उम्मीद नहीं थी। लेकिन इस बार सरकार तैयार है। जगह-जगह सुरक्षा बलों की चौकसी इस तैयारी को ही इंगित कर रही है। शायद यही वजह है कि इस बार राजनीति चाहे जितनी हो ले, पिछली बार की तरह हिंसक विरोध की गुंजाइश नहीं है।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

महोपनिषद् (भाग-31)

गतांक से आगे...

सर्वरूप परब्रह्म परमेश्वर को ज्ञान के नेत्रों से देखा जा सकता है, जिसके पास ज्ञान के नेत्रों का अभाव है, वह अविनाशी ब्रह्म को ठीक वैसे ही नहीं देख सकता, जिस प्रकार अंधे व्यक्ति को प्रकाशमान सूर्य (सवितादेवता) के दर्शन नहीं होते। वह ब्रह्म प्रज्ञान स्वरूप है।

सत्य ही प्रज्ञान का लक्षण है। अत: ब्रह्म के परिज्ञान से ही मर्त्य जीव अमरत्व को प्राप्त करता है। उस कार्य- कारण स्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार होते ही मनुष्य के हृदय की गाँठें खुल जाती हैं, सभी संशय समाप्त हो जाते हैं और समस्त कर्म (प्रारब्धादि) क्षीणता को प्राप्त हो जाते हैं।

हे पुत्र निदाघ! अनात्म भाव को त्यागकर, सांसारिक स्थिति में विकाररहित होकर अनन्य निष्ठापूर्वक अन्त: में प्रतिष्ठित होकर आत्म-चैतन्य में ही रमण करते रहो। जिस प्रकार मरुभूमि में भ्रम से दिखाई देने वाला जल मरुस्थल मात्र ही रहता है, उसी प्रकार जाग्रत, स्वप्न एवं सुषुप्तावस्था से युक्त यह सम्पूर्ण जगत् आत्मविचार से ही चिन्मय जानना चाहिए।

जो लक्ष्य एवं अलक्ष्य बुद्धि का परित्याग करके केवल आत्मनिष्ठ हो जाता है, वही श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी एवं स्वयं साक्षात् शिवरूप है। इस जगत् का अधिष्ठान अद्वितीय है, वाणी एवं मन की पहुँच से परे है। नित्य, विभु, सर्वगत, सूक्ष्मातिसूक्ष्म एवं अव्यय स्वरूप से युक्त है।

यह विश्व सर्वशक्तिमान् भगवान् महाशिव का मनोविलास मात्र ही है। संयम (धारणा, ध्यान, समाधि) एवं असंयम (सहज ज्ञान) के द्वारा ये सभी सांसारिक प्रपञ्च शान्ति को प्राप्त होते हैं। हे निदाघ मुने! मैं तुम्हारे मन में प्रादुर्भूत होते हुए विकारों की चिकित्सा के लिए उपाय बतलाता हूँ।

क्रमश: ...

नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस

दयानिधि

नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस, हर वर्ष 14 मार्च को मनाया जाता है। यह एकजुटता के लिए समर्पित एक दिन है, जब दुनिया भर के अलग-अलग समुदाय एक साथ आकर नदियों के महत्व के बारे में बात करते हैं। हर दिन 20 लाख टन सीवेज, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट दुनिया भर में पानी में छोड़े जाते हैं, यह 6.8 अरब लोगों की पूरी मानव आबादी के वजन के बराबर है। इसलिए अब समय आ गया है कि हम मानवता की भलाई के लिए अपनी नदियों को बचाएं।

सभ्यताएं नदियों के आसपास विकसित हुईं और वे हमारे जीवन और पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए अहम हैं। हालांकि ताजे पानी के पारिस्थितिक तंत्र इतने महत्वपूर्ण हैं, वे दुनिया में सबसे ज्यादा खतरे में हैं। मीठे या ताजे पानी की प्रजातियों में 1970 के बाद से 83 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है, जो कि स्थलीय या समुद्र के भीतर अनुभव की गई दर से दोगुनी है। उन्हें हमारी मदद की जरूरत है, उन्हें हमारी आवाज की जरूरत है।

नदियों के लिए कार्रवाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, नदियों के बारे में लोगों को जागरूक बढ़ाने के लिए बनाया गया एक दिन है। यह दिन नदियों के प्रबंधन, प्रदूषण, और संरक्षण से जुड़े मुद्दों को हल करने से संबंधित है।

अंतर्राष्ट्रीय नदी संगठन के मुताबिक, मार्च 1997 में कूर्टिबा, ब्राजील में बांधों से प्रभावित लोगों की पहली अंतर्राष्ट्रीय बैठक ने बांधों के खिलाफ और नदियों, जल और जीवन के लिए कार्रवाई के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मंजूरी दी। 20 देशों के नदी विशेषज्ञों द्वारा 14 मार्च को नदियों के लिए कार्रवाई दिवस घोषित किया गया था। प्रतिभागियों का उद्देश्य नदियों, जल के अन्य निकायों और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील वाटरशेड क्षेत्रों के क्षरण के खिलाफ एकजुट होना था।

भारत एक ऐसा देश है जहां नदियों की पूजा की जाती है, लेकिन प्रदूषण एक प्रमुख मुद्दा है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु और कावेरी जैसी नदियां देवताओं के रूप में पूजनीय हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय नदी घाटियों में आर्द्रभूमि की बहाली और रखरखाव के साथ-साथ नदी प्रदूषण की इन समस्याओं को को हल करने की बात करता है । नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसे देश का प्रदूषण प्रहरी खा जाता है, ने पहले ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय से अनुरोध कर चुका है कि वह देश के दूषित नदी क्षेत्रों की सफाई के लिए एक रणनीति तैयार करे।

यह एक ऐसा दिन है जो पानी के हमारे जीवनदायी स्रोत को बचाने, जश्न मनाने और अपने आसपास के लोगों को जागरूक करने के लिए समर्पित है। यदि नदियों को आर्थिक उद्देश्यों के लिए संरक्षित और उपयोग करना है, तो एकजुटता महत्वपूर्ण है और लोगों को सीमाओं के पार नदी प्रबंधन के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।

अफगानिस्तानियों को धोखा देने का साधन है डूरंड रेखा

मनीष राय

पिछले महीने तालिबान के उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास स्टानिकजई ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेते हुए कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच आधिकारिक सीमा का अभाव है। उन्होंने आगे कहा कि अफगानिस्तान कभी भी डूरंड रेखा को पाकिस्तान के साथ अपनी आधिकारिक सीमा के रूप में मान्यता नहीं देगा। पहले भी वरिष्ठ तालिबान नेताओं ने डूरंड रेखा की वैधता पर सवाल उठाए हैं जैसे - रक्षा मंत्री मौलवी मुहम्मद याकूब मुजाहिद ने पिछले साल कहा था कि डूरंड रेखा महज एक %रेखा% है। मौलवी याकूब ने यह भी कहा कि जब अफगान लोग चाहेंगे तो अफगानिस्तान इस मामले को इस्लामाबाद के सामने उठाएगा। जबसे काबुल में तालिबान सत्ता में आया है, विवादित सीमा के दोनों ओर के सैनिकों ने कई मौकों पर एक-दूसरे पर गोलीबारी की है, जिससे दोनों पक्षों को नुकसान हुआ है। ये सीमा विवाद कोई नई बात नहीं है; यह पाकिस्तान के निर्माण के तुरंत बाद ही अस्तित्व में आया। 1947 में जब पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ, तो अफगानिस्तान इसकी सदस्यता के खिलाफ मतदान करने वाला एकमात्र सदस्य राष्ट्र था। अफ़गानों ने तर्क दिया कि जब तक विवादित सीमा की समस्या अनसुलझी रहेगी तब तक पाकिस्तान को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। यह कहना सही होगा कि डूरंड रेखा मुद्दा पाकिस्तान के जन्म के बाद से अफगान-पाकिस्तान संबंधों की अप्रत्याशित प्रकृति को जटिल बनाता रहा है।

आइए इस विवादास्पद सीमा रेखा की उत्पत्ति पर एक नज़र डालें। उन्नीसवीं सदी के दौरान मध्य एशिया में बढ़ते रूसी विस्तारवाद और प्रभाव ने भारत में ब्रिटिश अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी। इसके परिणामस्वरूप दोनों साम्राज्यों के बीच कई राजनीतिक और कूटनीतिक टकराव हुए, जिसे बाद में द ग्रेट गेम के नाम से जाना गया। ट्रांस-कैस्पियन रेलवे का निर्माण, विशेष रूप से 1890 में निर्मित विस्तार, जो गोशगी में अफगान सीमा तक पहुंच गया था, ब्रिटिश राज (भारत सरकार) के लिए चिंता का एक और स्रोत था, क्योंकि यह रूस को अफगानिस्तान में बड़ी सेना लाने में सक्षम कर सकता था। रूस भी मध्य एशिया में ब्रिटिश वाणिज्यिक और सैन्य छापे से भयभीत था, जबकि ब्रिटेन चिंतित था कि रूस कहीं अपने विशाल क्षेत्र में भारत को शामिल ना कर ले। परिणामस्वरूप, दोनों साम्राज्यों के बीच संदेह, अविश्वास और युद्ध के स्थायी भय का माहौल पैदा हो गया। इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने अफगानिस्तान के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया जो एंग्लो-अफगान युद्ध के रूप में प्रसिद्ध है। हालाँकि, वे अफगानिस्तान पर सीधा नियंत्रण करने में विफल रहे। इसलिए, उन्होंने देश को एक बफर राज्य में बदलकर इस मुद्दे को कुछ हद तक सुलझाया।

लेकिन चूंकि यह रणनीति पर्याप्त सुरक्षित या आशाजनक नहीं थी, साथ ही अफगान विदेश नीति को नियंत्रित करने के लिए, अंग्रेजों का मानना था कि अफगानिस्तान की बाहरी सीमाओं को परिभाषित करना महत्वपूर्ण है। लेकिन किसी भी औपचारिक सीमा समझौते पर जाने से पहले अंग्रेजों का लक्ष्य अपनी आर्थिक, भू-राजनीतिक और रणनीतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए जितना संभव हो उतना क्षेत्र पर कब्जा करना था। अफ़ग़ानिस्तान को उसकी अधिकांश ज़मीन से अलग कर दिया गया और जो कुछ बचा था उस पर उसे कमज़ोर प्रशासनिक नियंत्रण के साथ छोड़ दिया गया। पर्याप्त भूमि हड़पने के बाद, भारत के विदेश सचिव सर मोर्टिमर डूरंड, अफगानिस्तान की सीमा के सीमांकन पर अफगानिस्तान के अमीर के साथ बातचीत शुरू करने के लिए 2 अक्टूबर 1893 को काबुल पहुंचे। अंतत:, बातचीत के परिणामस्वरूप डूरंड रेखा का निर्माण हुआ जिसने पश्तून आबादी के आधे हिस्से को संस्कृति, इतिहास और रक्त से घनिष्ठ रूप से विभाजित कर दिया। लेकिन डूरंड रेखा कभी भी वास्तविक सीमा के रूप में काम नहीं करती थी क्योंकि समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद सर डूरंड ने स्वयं कहा था- भारतीय पक्ष की जनजातियों को ब्रिटिश क्षेत्र के भीतर नहीं माना जाएगा। वे केवल तकनीकी अर्थ में हमारे प्रभाव में हैं इसे तब और स्पष्ट किया गया जब वायसराय, लॉर्ड एल्गिन ने 1896 में लिखते हुए कहा- डूरंड रेखा ब्रिटिश सरकार और अमीर के संबंधित प्रभाव क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए एक समझौता था। इसका उद्देश्य यथास्थिति को बरकरार रखना और अमीर की स्वीकृति प्राप्त करना था।

प्रत्येक अफगान सरकार का तर्क रहा है कि यह रेखा वैध सीमा नहीं है, क्योंकि इसका उद्देश्य केवल नियंत्रण रेखा होना था, जिसने सुरक्षा के लिए क्षेत्र को प्रभाव क्षेत्रों में विभाजित किया था। काबुल की ओर से एक और दावा, जो सीमा की वैधता को अस्वीकार करता है, वह यह है कि सीमा समझौते पर दबाव में हस्ताक्षर किए गए थे। हालाँकि कई इतिहासकार इस बात का प्रमाण देते हैं कि अमीर को समझौते के सार और परिणामों के बारे में पूरी जानकारी थी। लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आमिर को आर्थिक प्रतिबंध की धमकी के तहत इस पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। इसके अलावा, अब्दुर रहमान खान अपने क्षेत्र में ब्रिटेन और रूस के बीच युद्ध से बचना चाहते थे, जिसके अनिवार्य रूप से अफगानिस्तान के लिए विनाशकारी परिणाम होते। उस समय की वैश्विक महाशक्ति यानी ब्रिटेन के दबाव का सामना करते समय देश के पास बातचीत के लिए बहुत कम जगह थी।

अफगान अधिकारियों ने हमेशा अपने ब्रिटिश समकक्षों से इस सीमा विवाद को सुलझाने के लिए व्यापक बातचीत के लिए कहा, लेकिन सभी अनुरोध अनसुने कर दिए गए। और जैसे ही ब्रिटेन भारत छोड़ने के लिए तैयार हुआ, अफगानिस्तान ने फिर से सीमा में संशोधन की मांग की। अफगानों की इस माँग को भी अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद, अफगानिस्तान ने घोषणा की कि पिछले सभी डूरंड रेखा समझौते, जिसमें इसे कायम रखने वाली पूर्व एंग्लो-अफगान संधियाँ भी शामिल हैं, अमान्य हैं। इसके अलावा, अफगान संसद ने 1949 में डूरंड रेखा को धोखाधड़ी से खींची गई अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में निंदा करते हुए एक प्रस्ताव जारी किया। संक्षेप में यह कहना सही होगा कि किसी भी अफगान सरकार या राजनीतिक दल ने डूरंड रेखा को पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया। लेकिन 1970 के दशक के अंत में जब अफ़ग़ानिस्तान एक युद्धग्रस्त देश बन गया तो इस सीमा विवाद को अफ़गानों ने गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि वे आपस में लड़ने में बहुत व्यस्त थे।

पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान में अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए यह एक आदर्श स्थिति थी और यहां तक कि इस्लामाबाद अफगानिस्तान को अपना पांचवां प्रांत भी कहने लगा था। पाकिस्तान कभी भी अपने मामलों को नियंत्रित करने वाला एक गतिशील और शक्तिशाली अफगान राज्य नहीं चाहता। क्योंकि स्थिर और सुरक्षित अफगानिस्तान पाकिस्तान को अपने घरेलू मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं करने देगा और इस्लामाबाद के साथ वर्तमान सीमा रेखा स्वीकार भी नहीं करेगा। पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि डूरंड रेखा कोई सुलझा हुआ मुद्दा नहीं है और वे एकतरफा कुछ भी घोषित नहीं कर सकते। डूरंड रेखा विवाद केवल एक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर विवाद नहीं है, बल्कि अफगानों के लिए पहचान, जातीयता और संप्रभुता का विवाद है। जब तक दोनों राज्य उपरोक्त मामलों पर आम सहमति पर नहीं पहुंचते, यह विवादास्पद और विवादित सीमा रेखा दोनों पक्षों में दुश्मनी पैदा करती रहेगी।

आज का इतिहास

1941 ब्रिटेन ने बुल्गारिया के साथ कूटनीतिक संबंधों को तोड़ा।
1955 राजकुमार महेंद्र नेपाल के राजा बने।
1972 इतालवी प्रकाशक गियानियाकोमो फेल्ट्रेलीली, बोरिस पास्टर्नक के उपन्यास डॉक्टर झिवागो के अनुवाद और प्रकाशन के लिए जाने के लिए जाने जाते हैं, इसे सोवियत संघ से बाहर तस्करी के बाद ले जाया गया था।
1978 इजरायल-लेबनानी संघर्ष-इजरायल रक्षा बलों ने लिटानी पर आक्रमण किया, दक्षिणी लेबनान पर आक्रमण किया और कब्जा कर लिया, और लिटानी नदी के उत्तर में सैनिकों को धक्का दे दिया।
1983 तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक ने 23 साल में पहली बार तेल कीमतों में कटौती की।
1988 गणित प्रेमियों के लिए खास दिन पाई डे पहली बार मनाया गया।
1988 चीन ने एक नौसैनिक युद्ध में वियतनाम को हरा दिया क्योंकि स्प्रैटली द्वीपों पर समुद्र संबंधी अवलोकन पोस्ट स्थापित करने के लिए पूर्व निर्धारित किया गया था।
1989 दक्षिण अफ्रीकी नेशनल पार्टी द्वारा पीटर बोथा के स्थान पर एफ.डब्ल्यू.डी. क्लार्क को राष्ट्रपति बनाया गया।
1990 श्रीमती अर्था पास्कल ट्राविल हैती की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनीं।
1991 बर्मिंघम सिक्स, जिसे गलत तरीके से 1974 में इंग्लैंड के बर्मिंघम पब बम विस्फोटों का दोषी ठहराया गया था, को सोलह साल की जेल के बाद रिहा किया गया था।
1994 मैक्सिकन बैंकर/अरबपति अल्फ्रेडो हार्प हेलू का अपहरण कर लिया गया था।
1995 पहली बार, अंतरिक्ष में 13 लोग हैं।
1997 ईरानी सैन्य विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 80 लोग मारे गए थे।
1997 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता माइकल जॉनसन ने 67 वां जेम्स ई। सुलिवन पुरस्कार जीता।
1997 राष्ट्रपति क्लिंटन यात्राएं करते हैं और सर्जरी की आवश्यकता वाले घुटने को फाड़ते हैं।
2004 चीन में निजी सम्पत्ति को क़ानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन हुआ।
2008 विक्ट्री समूह ने ब्रिटेन की प्रसिद्ध स्विचगियर निर्माता कंपनी क्रेग एण्ड डेरिकार का अधिग्रहण किया।
2008 तिब्बत में ल्हासा और अन्य जगहों पर दंगों, विरोध प्रदर्शनों और प्रदर्शनों की एक श्रृंखला शुरू हुई।

कांग्रेस से पलायन को देखते रहना मजबूर क्यों हैं पार्टी के आला नेता?

ललित गर्ग

कांग्रेस के दिग्गज एवं कद्दावर नेताओं में नाराजगी, हताशा एवं राजनीतिक नेतृत्व को लेकर निराशा के बादल लगातार मंडरा रहे हैं, पार्टी लगातार बिखराव एवं टूटन की ओर बढ़ रही है। पार्टी में उल्टी गिनती चल रहा है, लेकिन आश्चर्य इस बात को लेकर है कि इस उल्टी गिनती को रोकने के लिए कोई मजबूत उपाय नहीं हो रहे हैं। पार्टी से एक के बाद एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस का दामन छोड़ने में लगे हुए हैं, कांग्रेस छोड़ने वाले इन नेताओं में कुछ राहुल गांधी के खास रहे हैं तो कुछ सोनिया गांधी के। पहले कांग्रेस में गिनती वन, टू, श्री से होती थी। आजकल श्री, टू, वन से होती है। पार्टी को मजबूती देने एवं पार्टी छोड़ कर जाने वाले नेताओं को रोकने की गिनती कौन शुरू करेगा? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पहले देश में एकता यात्रा और उसके बाद अब न्याय यात्रा निकाल रहे हैं लेकिन वे पार्टी के भीतरी असंतोष एवं निराशा को रोकने का अभियान क्यों नहीं शुरू करते? क्या गांधी परिवार का अहंकार एवं परिवारवादी सोच ही पार्टी के टूटने का कारण है?

आगामी लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में बीते कुछ समय से शायद ही कोई दिन ऐसा बीतता हो, जब किसी कांग्रेस नेता के पार्टी छोड़ने की खबर न आयी हो। गत दिवस गांधी परिवार के करीबी माने जाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी एवं पूर्व कांग्रेसी सांसद गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी समेत मध्य प्रदेश के कई कांग्रेसी नेता भाजपा में शामिल हो गए। इसके पहले गुजरात, असम, महाराष्ट्र और यहां तक कि केरल के भी नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। एक के बाद एक नेताओं के कांग्रेस छोड़ने का सिलसिला यही बताता है कि उन्हें पार्टी में अपना भविष्य नहीं दिख रहा है, पार्टी नेतृत्व की अपरिपक्व एवं बचकाना राजनीति एवं देश-विकास की कोई स्पष्ट नीति न होना भी इन नेताओं के पार्टी छोड़ने का कारण है। राहुल गांधी के पास प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं भाजपा के खिलाफ कोई मजबूत विरोधी दावे नहीं हैं, चुनाव जीतने के लिये जिस तरह की राजनीति सोच एवं एजेंडा होना चाहिए, वह भी दिखाई नहीं दे रहा है। जातीय जनगणना, अदाणी- अंबानी, युवाओं, महिलाओं एवं गरीबों की अनदेखी करने के खोखले एवं बेबुनियाद आरोप के अलावा और कुछ कहने को नहीं है। वे जिन समस्याएं की चर्चा करते हैं, उनका कोई कारगर समाधान उनके पास नहीं हैं। अक्सर वे समाजवादी और वामपंथी नीतियों की वकालत करते दिखते हैं, जो पहले ही नाकाम हो चुकी हैं। कांग्रेस की यह विडम्बनापूर्ण एवं बेजान स्थिति तब है, जब आम चुनावों की घोषणा होने ही वाली है। कांग्रेस से लगातार पलायन करते नेताओं की यह दर्दनाक स्थिति रेखांकित करती है कि पार्टी नेतृत्व अपने नेताओं को प्रेरित एवं रोक नहीं कर पा रहा है। इसके लिए सबसे अधिक दोषी राहुल गांधी और उनके इर्द-गिर्द के लोग हैं, जो भाजपा एवं मोदी सरकार को चुनौती देने के नाम पर घिसे-पिटे बयान देने में लगे हुए हैं।

लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस को रोज एक न एक झटका लग रहा है। उसके नेता कब उसका साथ छोड़ दें पता नहीं चलता। जैसे ही कोई चुनाव शुरू होता है, उसी समय से नेताओं का कांग्रेस छोड़कर जाना शुरू हो जाता है। क्या महाराष्ट्र, क्या मध्य प्रदेश, क्या कर्नाटक, सभी राज्यों से कांग्रेस के कई बड़े नेता या तो पार्टी छोड़ चुके हैं या छोड़ने की अटकलें लग रही हैं। राहुल गांधी के सबसे नजदीकी नेताओं में

शामिल रहे दिग्गज भी अब भाजपा के साथ हैं तो वहीं कांग्रेस में सोनिया गांधी के करीबी माने जाने वाले नेताओं में से रीता बहुगुणा जोशी, कैप्टन अमरिंदर सिंह और गुलाम नबी आजाद भी बहुत पहले ही पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं। कांग्रेस से युवा नेताओं का भी मोह भंग होता जा रहा है। इसका उदाहरण मिलिंद देवड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, अल्पेश ठाकोर, हार्दिक पटेल, सुष्मिता देव, प्रियंका चतुर्वेदी, आरपीएन सिंह, अशोक तंवर जैसे नेता हैं, जो कांग्रेस से अलग हो चुके हैं। बिहार में अशोक चौधरी, असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, सुनील जाखड़ के साथ अश्वनी कुमार, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हान जैसे भी नेता हैं जो पार्टी के काम करने के तरीके से नाखुश होकर पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं। ये वे नेता हैं जिन्हें कांग्रेस ने पहचान दी, केन्द्रीय मंत्री, राज्य में मंत्री बनाया, पार्टी में बड़े पदों पर बिठाया परन्तु पार्टी के मुश्किल वक्त में वो पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं।

कांग्रेस के दिग्गज नेता जो पार्टी छोड़ चुके या छोड़ने की फिराक में है, वे नरेन्द्र मोदी एवं राहुल के बीच के फर्क को महसूस कर रहे हैं। कांग्रेसी नेता यह गहराई से देख रहे हैं कि राहुल किस तरह हमारे सैनिकों की वीरता-शौर्य-बलिदान पर सवाल उठाते रहे हैं, भारत की बढ़ती साख, सुरक्षा एवं विकास की तस्वीर को बट्टा लगाते हैं। इन नेताओं ने महसूस किया कि किन्हीं राहुल रूपी गलतबयानी की वजह से मोदी की छवि पर कोई असर नहीं पड़ा है, भारत ही नहीं, समूची दुनिया में मोदी के प्रति सम्मान एवं श्रद्धा का भाव निरन्तर प्रवर्द्धमान है। राहुल गांधी एवं उनके रणनीतिकारों की नरेंद्र मोदी, भाजपा और संघ परिवार के प्रति शाश्वत वैर-भाव एवं विरोध की राजनीति समझ में आती है लेकिन देश की छवि खराब करने, सरकार को कमजोर बता कर और मोदी जैसे कद्दावर नेता को खलनायक बनाने से उन्हें इज्जत नहीं मिलेगी। यह तो विरोध की हद है! नासमझी एवं राजनीतिक अपरिपक्वता का शिखर है!! उजालों पर कालिख पोतने के प्रयास हैं! इसकी कीमत कांग्रेस पार्टी अपने कद्दावर नेताओं को खोकर दे रही है।

दरअसल भाजपा के ताकतवर होने के बाद कांग्रेस ने कभी भी पार्टी के लगातार कमजोर पड़ते जाने को लेकर आत्मंथन नहीं किया। कांग्रेस नीति और सिद्धांत भी संदेहास्पद होते चले गये हैं। ऐसे में भाजपा ने कांग्रेस के मजबूत किले में तोडफ़ोड़ करने में कसर बाकी नहीं रखी। भाजपा ने दोतरफ से कांग्रेस का घेराव किया। एक तरफ कांग्रेस शासन के भ्रष्टाचार और गलत नीतियों को न सिर्फ उजागर किया बल्कि कई दिग्गजों पर सीबीआई और ईडी की कार्रवाई भी करवाई। दूसरी तरफ भाजपा ने कांग्रेस में सेंधमारी करके उसके मजबूत नेताओं को तोड़ा और पार्टी को हाशिए पर ले आयी। दोनों तरफ से पिटती कांग्रेस में नेताओं को लगने लगा कि इसके दिन लद गए लगते हैं, यहां उनका राजनीतिक जीवन अंधकारमय है। राहुल गांधी अपने आधे-अधूरे, तथ्यहीन एवं विध्वंसात्मक बयानों को लेकर निरन्तर चर्चा में रहते हैं। उनके बयान हास्यास्पद होने के साथ उद्देश्यहीन एवं उच्छृंखल भी होते हैं। राहुल ने पहले भी बातों-बातों में मोदी विरोध के नाम पर राष्ट्र-विरोध किया है। वह देश के प्रमुख विपक्षी दल के नेता हैं। सरकार की नीतियों से नाराज होना, सरकार के कदमों पर सवाल उठाना उनके लिए जरूरी है। राजनीतिक रूप से यह उनका कर्तव्य भी है। लेकिन उनके विरोध एवं राजनीति में वह दम-खम नहीं है जो मोदी का मुकाबला कर सके। यही बात कांग्रेस पार्टी के अंदर अभी जो हलचल है उसका एक बड़ा कारण है। वैसे कांग्रेस की अंतर्कलह की वजहें काफी सालों से हैं जिसको सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अब मल्लिकार्जुन खरगे तक रोकने में असक्षम दिख रहे हैं। भले ही कांग्रेस के कुछ चाटुकार नेता पार्टी से पलायन का कारण केन्द्रीय एजेंसियों का दबाव और इसे ही भाजपा में जाने का कारण बतायें। अगर कांग्रेस का केन्द्रीय नेतृत्व इतना प्रभावी एवं सक्षम होता तो वे अपने जाने वाले नेताओं को रोकते हुए कहते कि ये वक्त किसी दबाव के आगे झुकने का नहीं है बल्कि लोकतंत्र को बचाने और देश के भविष्य के लिए संघर्ष करने का है। कांग्रेस तो इतनी जर्जर एवं आधारहीन हो गयी है कि उसने पूरे देश में विपक्ष को एनडीए के खिलाफ इकठ्ठा करने के लिए इंडिया गठबंधन तैयार किया, तब उसे लगा था कि देश की सत्ता तक पहुंचने के लिए यह रास्ता आसान होगा। लेकिन, एक-एक कर इंडिया गठबंधन से पार्टियां अलग होती चली गईं। सबसे पहले नीतीश कुमार जिन्होंने इस गठबंधन के लिए सबको इकट्ठा किया था भाजपा के साथ हो लिए। फिर ममता बनर्जी को भी कांग्रेस का साथ रास नहीं आया। इसके मायने तो यही हैं कि कांग्रेस खुद की पार्टी एवं इंडिया गठबंधन को संभालने में ही नाकाम रही तो वह देश क्या संभालेगी?

क्या प्रियंका नहीं उतरेंगी रायबरेली के सियासी मैदान में?

आशीष तिवारी

कांग्रेस प्रत्याशियों की दो सूचियां आ चुकी हैं। राजस्थान, मध्यप्रदेश और असम जैसे राज्यों में कई प्रत्याशियों की घोषणा भी हो चुकी है। लेकिन अब तक उत्तर प्रदेश की 17 सीटों पर एक भी प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की भी हो रही है कि संभवतया राहुल गांधी इस बार अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। जबकि रायबरेली से प्रियंका गांधी की जीत की दावेदारी को खूब टटोला जा रहा है। आलम यह है कि प्रदेश नेतृत्व ने भले ही प्रियंका गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ने की सिफारिश की हो, लेकिन रायबरेली में कांग्रेस की ओर से अभी भी फोन के माध्यम से प्रियंका गांधी के लिए सेफ सीट का सर्वे किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने अब तक दो बार अलग-अलग राज्यों में लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। लेकिन कांग्रेस के दो बड़े नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर अटकलें जारी हैं। उत्तर प्रदेश जैसे प्रमुख राज्य में अब तक कांग्रेस की ओर से सीटों के न घोषित किए जाने को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। सियासी गलियारों में यहा तक कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी की सीट को लेकर पार्टी अभी भी आश्वस्त नहीं है कि उनको मैदान में उतरा जाए या न लड़ाया जाय। यही वजह है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी और अमेठी से राहुल गांधी को प्रत्याशी बनाए जाने पर संशय बना हआ है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की ओर से अभी तक अपने दो प्रमुख नेताओं के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने को लेकर कोई भी आधिकारिक जानकारी तो नहीं दी गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की ओर से राहुल और प्रियंका को चुनाव लड़ने जाने का प्रस्ताव भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी अभी भी यह टटोलने में लगी है कि क्या पहली बार चुनाव लड़ने वाली प्रियंका गांधी के लिए रायबरेली सुरक्षित सीट होगी या नहीं। जानकारी के मुताबिक रायबरेली में लोगों से फोन के माध्यम से सीट की मजबूती को लेकर सर्वे भी किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सर्वे में प्रियंका गांधी की मजबूत दावेदारी को लेकर सीधा सवाल पूछा जा रहा है। हालांकि पार्टी ने इससे पहले भी रायबरेली में एक सर्वे कराया था। कांग्रेस पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अभी तक की रिपोर्ट में रायबरेली की स्थानीय जनता की ओर से गांधी परिवार से किसी को भी प्रत्याशी बनाए जाने पर जीत का आश्वसन मिला है। लेकिन सियासी गलियारों में कहा यही जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अभी भी उहापोह की स्थिति में है कि क्या प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारा जाए या नहीं। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक जानकार बृजेंद्र शुक्ला कहते हैं कि गांधी परिवार के लिए रायबरेली और अमेठी कितनी सुरक्षित है यह तो पिछले चुनाव में अमेठी से पता चल गया है। क्योंकि रायबरेली में सोनिया गांधी खुद प्रत्याशी थीं इसलिए वह सीट कांग्रेस के खाते में आई। उनका कहना है बीते कुछ समय से गांधी परिवार खासतौर से राहुल गांधी ने अमेठी से जरूर कुछ दूरी बना ली थी। संभव है कि वह चुनाव हार गए थे, इसलिए उनका ध्यान अपने नए लोकसभा क्षेत्र वायनाड में बीता। इसलिए राहुल गांधी अमेठी सीट पर इस बार चुनाव लड़ेंगे, इसलिए इस पर संशय बना हुआ है। रही बात प्रियंका गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की तो, यह सीट तभी सुरक्षित होगी जब इस पर गांधी परिवार से कोई चुनावी मैदान में उतरेगा।

पाकिस्तान, बांग्लादेश के हिन्दू, सिखों और बौद्धों का विरोध क्यों?

संजय तिवारी

भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता की राजनीति करनेवाले दल भारत के हिन्दुओं का विरोध करते करते अब पाकिस्तान और बांग्लादेश पहुंच गये हैं। वो नहीं चाहते कि वहां के सताये हुए हिन्दू, बौद्ध, सिख या ईसाइयों को भारत में जीवन जीने की जगह मिले। यही कारण है कि जब केन्द्र की मोदी सरकार ने 2019 नागरिकता संशोधन कानून पास किया तो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सहित अनेक दलों ने आसमान सिर पर उठा लिया। यह जानते हुए भी कि इसका भारत के नागरिकों से कुछ लेना देना नहीं है फिर वो चाहे जिस धर्म या मजहब के हों, फिर भी यह भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया कि इस कानून के जरिए मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है।

तर्क यह भी दिया गया कि अगर पड़ोसी देशों के हिन्दुओं, सिखों, बौद्धों या फिर ईसाइयों को भारत में नागरिकता की सहुलियत दी जा रही है तो मुसलमानों को क्यों अलग किया जा रहा है? इस तर्क को गढनेवाले भूल गये भारत के पड़ोस में मुख्य रूप से तीन देश जहां के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता देने का कानून बनाया गया है वो इस्लामिक देश हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि इस्लामिक देशों में भी मुसलमानों की प्रताड़ना हो रही है? मुस्लिम कम्युनिटी में अनेक फिरके हैं। शिया सुन्नी तो मुख्य रूप से अलग हैं ही। इसके अलावा शियाओं के फिरके अलग हैं और सुन्नियों के अलग। इनमें भारतीय उपहाद्वीप में मुख्य रूप से बरेलवी और देओबंदी सुन्नी बसते हैं। फिर बहुत छोटी संख्या अहमदिया मुसलमान और सूफियों की भी है। लेकिन मुश्किल यह है कि इस्लाम में हर फिरका अपने आप को जन्नती तो दूसरे फिरके को जहन्नमी करार देता है।

अहमदिया कम्युनिटी से तो पाकिस्तान में मुसलमान होने का हक भी छीन लिया गया है। मुस्लिम होने के बावजूद उन्हें मॉइनॉरिटी में रखा गया है क्योंकि वो इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद को इकलौता पैगंबर मानने की बजाय इस फिरके को शुरु करनेवाले मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को भी पैगंबर मानते हैं। वो मानते हैं कि इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद आखिरी नबी नहीं है बल्कि नबूवत का

सिलसिला जारी है। यही कारण है कि सुन्नी और शिया मुसलमान अहमदिया को मुसलमान ही नहीं मानता। पाकिस्तान में निश्चित रूप से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। उनकी मस्जिदों को तोड़ दिया जाता है। उनसे %खत्म ए नबूवत% के फार्म पर साइन करवाये बिना कोई सरकारी सुविधा नहीं दी जाती। पाकिस्तान के पंजाब इलाके में रहनेवाले इन मुसलमानों को लाहौरी या कादियानी मुसलमान भी कहा जाता है जो अधिकांश अपनी पहचान छिपाकर रहते हैं। पाकिस्तान में किसी को अहमदिया, कादियानी या लाहौरी मुसलमान घोषित करने का मतलब गाली देने जैसा है।

जो लोग नागरिकता कानून के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश के माइनारिटी मुसलमानों का सवाल जोड़ रहे हैं क्या वो चाहेंगे कि अहमदिया मुसलमानों को भारत में शरण या नागरिकता दी जाए? यह सवाल आते ही भारत के मुसलमान भी बगले झांकने लगता है क्योंकि यहां का मुसलमान भी अहमदिया को मुसलमान नहीं मानता है। फिर सवाल है कि क्या अल्पसंख्यक मुसलमानों के नाम पर शिया मुसलमानों को नागरिकता कानूनों में शामिल कर लिया जाए? अगर ऐसा किया जाता है तो भारत का बहुसंख्यक सुन्नी मुसलमान ही इसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। वह कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान या बांग्लादेश के शिया मुसलमानों को भारत में नागरिकता दिया जाए। वह तो उस मुख्यधारा के सुन्नी मुसलमानों की भारत में आबादी बढ़ाना चाहता है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में शासन कर रहे हैं। इसलिए वह रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा सामने रख देता है जो इस कानून के दायरे से ही बाहर हैं। यहां एक बात ध्यान देने योग्य है कि अगर नागरिकता कानून में म्यामांर के अल्पसंख्यक नहीं हैं तो नेपाल के भी अल्पसंख्यक नहीं है। म्यामांर में अल्पसंख्यक रोहिंग्या शामिल नहीं किये गये हैं तो वहां के अल्पसंख्यक हिन्दू भी इस कानून के दायरे से बाहर हैं। इस कानून के दायरे में मुख्य रूप से पाकिस्तान और बांग्लादेश को इसलिए रखा गया है क्योंकि यही दो हिस्से हैं जिन्हें मजहब के नाम पर भारत से अलग किया गया था।

बंटवारे के समय भारत के मुसलमानों की एक सीमित आबादी भारत छोड़कर पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान चली गयी तो वहां की हिन्दू आबादी भागकर भारत आ गयी। फिर भी न तो पूरी तरह से भारत के मुसलमान इस्लामिक देशों में गये न ही पूरी तरह से वहां के हिन्दू भारत आये। सिर्फ पंजाब के दोनों हिस्सों में ऐसा हुआ कि पूर्वी पंजाब के लगभग सभी मुसलमान पाकिस्तान चले गये और पश्चिमी पंजाब के लगभग सभी हिन्दू सिख भारत चले आये। सिन्ध से भी व्यापक आबादी भारत आ गयी लेकिन दूर दराज के जिलों में रहनेवाले गरीब हिन्दू परिवार वहीं रह गये। बंटवारे के समय दोनों ओर के लोगों को यही लगता था कि यह बंटवारा अस्थाई है और एक दिन आयेगा जब वो अपने घरों की ओर दोबारा लौट आयेंगे।

बांग्लादेश में जरूर पाकिस्तान के मुकाबले हिन्दुओं की स्थिति बेहतर है लेकिन तभी जब शेख हसीना की अवामी लीग सत्ता में रहती है। वरना कट्टरपंथी सुन्नी मुसलमान आये दिन हिन्दुओं की संपत्ति और बहू बेटियों को निशाना बनाते ही हैं। जब पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश बना तब 1974 में वहां 13.5 प्रतिशत हिन्दू थे लेकिन 2022 में घटकर 7.9 प्रतिशत रह गये। निश्चित रूप से पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, अफगानिस्तान के बाद अब इन देशों में भी हिन्दू सिमट रहे हैं। इन इस्लामिक देशों की सरकारें चाहे जो कहें लेकिन मुल्ला बिरादरी के आगे सरकारें भी हार जाती हैं क्योंकि इस्लामिक देश में गैर मुस्लिमों को प्रताड़ित करना, उन्हें इस्लाम में दाखिल करना, उनकी बहू बेटियों को जबरन इस्लाम कबूल करवाकर निकाह कर लेना ये इस्लाम का कोर वैल्यू है जिससे कोई मुसलमान इंकार नहीं कर सकता। ऐसे में जो देश सच्चे इस्लाम को लागू करने की दिशा में आगे बढेगा वह मुसलमानों के अलावा बाकी सबको समाप्त करने को कभी गलत नहीं कहेगा।

घातक हो सकता है मायावती का अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय

डॉ. आशीष वशिष्ठ

बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने फिर एक बार आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर घोषणा की है कि बहुजन समाज पार्टी अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी। मायावती इसके पहले भी कई बार लोकसभा चुनाव के लिए किसी भी तरह के गठबंधन में शामिल होने से इंकार करती रही हैं। उन्होंने चुनाव के लिए अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा भी नहीं की है जिसके कारण उनके इंडिया गठबंधन में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। 2024 के आम चुनाव में राजनीतिक लिहाज से उत्तर प्रदेश जैसे अहम राज्य में हर राजनीतिक दल अधिक से अधिक सीटें हासिल करना चाहता है। इसलिए एनडीए और इंडिया गठबंधन में छोटे-बड़े दल शामिल होकर अपना राजनीतिक कद और हैसियत बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे में मायावती का किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनना कई प्रश्न खड़े करता है।

प्रश्न यह है कि क्या अकेले चुनाव लड़कर मायावती एनडीए और इंडिया गठबंधन को चुनौती दे पाएंगी? क्या मायावती को भरोसा है कि उनका कोर वोट बैंक पूरी तरह उनका साथ देगा? क्या मायावती को लगता है कि त्रिकोणीय मुकाबले में बसपा हावी रहेगी? क्या मायावती को इस बात का भरोसा है कि इंडिया गठबंधन की बजाय मुस्लिम मतदाता उनके साथ मजबूती से खड़े होंगे? क्या मायावती चुनाव नतीजों के हिसाब से रणनीति का खुलासा करेगी? क्या मायावती एकला चलो की राह पर हैं या फिर वो जिस तरह से खामोश हैं उसके पीछे कोई बड़ा प्लान है?

बसपा प्रमुख ने पिछले छह-सात महीने में अकेले चुनाव लड़ने की बात कई बार कही है, साथ ही यह भी कहा कि गठबंधन करने से उनको नुकसान होता है। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि कोई पार्टी गठबंधन नहीं करे और चुनाव अकेले लड़े। लेकिन पार्टी लड़ते हुए तो दिखाई दे! मायावती की बहुजन समाज पार्टी बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के साथ गठजोड़ कर चुकी है। लेकिन बीते ढाई दशकों से बसपा का

भाजपा के बीजेपी के प्रति ज्यादा रुझान देखा गया है। मायावती तीन बार भाजपा के सहयोग से यूपी की मुख्यमंत्री भी बन चुकी हैं।

बसपा ने पिछला लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिल कर लड़ा था लेकिन सपा की सहायता से शून्य से 10 सीट पर पहुंचने के बाद ही उन्होंने तालमेल समाप्त कर दिया था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बसपा का वोट बैंक भी खिसक रहा है। बसपा सुप्रीमो भले ही कहें कि गठबंधन से उनकी पार्टी को नुकसान होता है लेकिन सच्चाई तो ये है कि पिछले लोकसभा चुनाव में गठबंधन का सबसे ज्यादा लाभ बसपा को ही हुआ था। वर्ष 1996 में बसपा ने 6 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, तब बसपा को 20.6 प्रतिशत मत मिले थे। वर्ष 1998 में बसपा को चार सीटें मिलीं और वोट प्रतिशत बढ़कर 20.9 प्रतिशत हो गया। वर्ष 1999 में बसपा को 14 सीटें मिलीं और मत 22.08 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2004 में सीटें बढ़कर 19 हो गईं और 24.67 प्रतिशत मत मिले। बसपा ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वर्ष 2009 में किया जब पार्टी को 20 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हुई और 27.42 प्रतिशत मत मिले।

बसपा की स्थिति साल 2014 से बदलती चली गई। बीस सांसदों वाली बसपा को इस चुनाव में एक भी सीट हासिल नहीं हो पाई और उसका मत प्रतिशत भी गिरकर 19.77 प्रतिशत पर आ गया। बसपा के वोट में लगभग आठ प्रतिशत की गिरावट आई। 1996 के बाद बसपा का ये सबसे बुरा प्रदर्शन था। वर्ष 2019 में बसपा ने सपा के साथ गठबंधन किया। जिसका बसपा को भरपूर लाभ हुआ और शून्य सीटों वाली बसपा ने दस सीटों पर विजय प्राप्त की। जबकि उसका मत और कम हुआ। इस चुनाव में बसपा को सपा के साथ गठबंधन कर 19.43 प्रतिशत ही मत मिले। विधानसभा में बसपा का केवल एक विधायक है।

एक वो समय था जब बसपा चुनाव से काफी समय पहले ही उम्मीदवार घोषित कर देती थी। सबसे पहले संभवत: बसपा ने ही चुनाव से महीनों पहले उम्मीदवार घोषित करने शुरू किए थे। लेकिन अब चुनाव बिल्कुल सिर पर आ चुके हैं और बसपा उम्मीदवारों की घोषणा की बजाय अकेले चुनाव लड़ेंगे का पुराना रिकॉर्ड बजाए जा रही है। जबकि भाजपा, सपा, रालोद और सुभासपा कई सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। बड़ी मशक्कत के बाद बीते 10 मार्च को बसपा ने यूपी की मुरादाबाद सीट से मो. इरफान सैफी को अपना पहला प्रत्याशी घोषित किया है।

पिछले एक दशक में मायावती के कई भरोसेमंद सिपहसालार दूसरी पार्टियों में शामिल होते चले गए। बीते चुनाव में जीते 10 सांसद भी नई सियासी संभावनाएं तलाश रहे हैं। इसमें अंबेडकर नगर से सांसद रितेश पांडे बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उन्हें बीजेपी ने टिकट भी दे दिया है। वहीं गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी को सपा उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। वहीं, अमरोहा से दानिश अली अब कांग्रेस के खेमे में हैं। जौनपुर से सांसद श्याम सिंह यादव भी कांग्रेस की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। बिजनौर से सांसद मलूक नागर और लालगंज लोकसभा सीट से सांसद संगीता आजाद के भी पाला बदलने के कयास लगाए जा रहे हैं। यूपी समेत देश के अन्य राज्यों में बीएसपी का सियासी ग्राफ चुनाव दर चुनाव गिरता ही जा रहा है। पिछले वर्ष विधानसभा चुनावों में आकाश आनंद छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में पार्टी का चुनावी अभियान संभाल रहे थे, जहां पार्टी ने पिछले चुनाव की तुलना में काफी खराब प्रदर्शन किया है। राजस्थान छोड़कर किसी भी राज्य में बसपा का खाता तक नहीं खुला और वोट फीसदी में भी गिरावट आई। बसपा अब उत्तर प्रदेश और बाहर के राज्यों में हर जगह कमजोर दिखाई दे रही है।

जजपा से गठबंधन टूटने से भाजपा को होगा लाभ..!

विनोद पाठक

लोकसभा चुनाव से पहले जहां भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का कुनबा बड़ा करने में जुटी है, वहीं हरियाणा में उसने जननायक जनता पार्टी (जजपा) से राहें जुदा कर ली हैं। जजपा से गठबंधन तोड़ने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस्तीफा दे चुके हैं और शाम को पुन: भाजपा नेतृत्व की सरकार बनने जा रही है। दरअसल, जजपा से अलग होकर भाजपा ने कहीं न कहीं राजनीति की चतुर चाल चली है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जजपा एक या दो सीट मांग रही थी और प्रेशर पॉलिटिक्स की कोशिश कर रही थी, लेकिन पिछले कुछ समय से जजपा से अलग होने का बहाना ढूंढ रही भाजपा को मौका मिल गया। पहले हरियाणा की राजनीति में पिछले कुछ वर्षों से क्या चल रहा है? इसे समझते हैं। राज्य में कभी मुख्य सत्ताधारी पार्टी रही कांग्रेस पिछले नौ साल से विपक्ष में है। राज्य में जाट कांग्रेस का मुख्य वोटबैंक हैं। इसी जाट वोटबैंक में सेंध लगाकर वर्ष 2019 में युवा नेता दुष्यंत चौटाला ने नई नवेली जजपा को विधानसभा की 90 में से 10 सीटों पर जीत दिलाई थी। भाजपा को 41 सीटें, बहुमत से 5 सीटें कम, मिली थीं। कांग्रेस 30 सीटों पर रुक गई थी। उस समय दुष्यंत चौटाला एकाएक हीरो बनकर उभरे थे। तब 7 निर्दलीय, एक इनोलो और एक हलोपा का विधायक जीता था। कांग्रेस ने कुछ जोड़-तोड़ की कोशिश की थी, लेकिन दुष्यंत चौटाला को कांग्रेस के बजाय भाजपा के साथ जाने में फायदा दिखा था। फिर निर्दलीय भी भाजपा के पक्ष में थे। पहला, दुष्यंत चौटाला को पता था कि यदि वो कांग्रेस के साथ गए तो उन्हें वोटबैंक का नुकसान होगा। दूसरा, दुष्यंत को भाजपा के साथ रहने का लाभ यह दिखा कि सरकार में न केवल हिस्सेदारी अच्छे से मिलेगी, बल्कि केंद्र में भाजपा के रहने का लाभ भी पार्टी को मिलेगा। हालांकि, पिछले 4 साल में जजपा कोटे के मंत्रियों की कार्यशैली का विरोध हो रहा था। स्वयं उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर असहज थे। जजपा के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। यहां तक दुष्यंत चौटाला पर उन्हीं की पार्टी के नारनौल विधायक राजकुमार गौतम ने उंगली उठाई थी और विधानसभा में दोनों के बीच नोकझोंक हुई थी। अब वर्तमान के घटनाक्रम को समझते हैं। जजपा लोकसभा चुनाव में भाजपा से हिसार और महेंद्रगढ़-नारनौल सीट मांग रही थी, लेकिन भाजपा को पता था कि एक-दो सीटें जजपा को देने का कोई लाभ पार्टी को नहीं मिलने वाला है। खासकर जजपा के जाट वोटर भाजपा को वोट नहीं देंगे। भाजपा को यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जजपा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का ही वोट कटेगी, जिसका लाभ उसे मिलेगा। अब पूरी संभावना है कि लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 10 सीटों पर जजपा अकेले लड़ेगी। कांग्रेस भी मजबूती के साथ अपने प्रत्याशी उतार रही है। ऐसे में जाट वोटर बंटेगा। राज्य में जो समीकरण बन रहे हैं, उसमें नॉन जाट वोटर भाजपा की ओर शिफ्ट हो गया है। खासकर पंजाबी, ब्राह्मण और दलित वोटर भाजपा को सपोर्ट करता है। यदि जाट वोटर आपस में बंटता है तो उसका लाभ भाजपा को होने वाला है। राज्य में विधानसभा चुनाव आगामी नवंबर में होने हैं और निर्दलीयों के सहारे भाजपा सरकार चलती रहेगी। ऐसे में भाजपा के लिए यह गठबंधन टूटना फायदे का सौदा होगा। एक संभावना यह भी जताई जा रही है कि नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में इनेलो भाजपा के साथ आ सकती है। उसे गठबंधन में 90 में से 10-15 सीट मिल सकती हैं। इनेलो के पास 2-3 प्रतिशत जाट वोट बताया जाता है। कुछ सीटों पर भाजपा को लाभ इनेलो का लाभ मिल सकता है। हालांकि, इस गठबंधन को लेकर अभी कुछ कह पाना मुश्किल है।

इस शिव मंदिर के पत्थरों को थपथपाने से आती है डमरू की आवाज, एक बार कर आएं दर्शन

भारत में भगवान शिव के कई मंदिर हैं, और हर मंदिर की एक अलग कहानी है। कुछ मंदिरों के अपने इतिहास और रहस्य है। यहां हम बता रहे हैं एक ऐसे शिव मंदिर के बारे में जो हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में मौजूद है। इस मंदिर का नाम जटोली शिव मंदिर है। इसे एशिया के सबसे उंचे शिव मंदिरों में से एक माना जाता है। महाशिवरात्रि के दौरान यहां पर भक्तों की खूब भीड़ रहती है। यहां जानिए मंदिर से जुड़ी कुछ बातें-

कहते हैं कि भगवान शिव ने इस जगह पर तपस्या की थी। फिर बाद में यहां स्वामी परमहंस आए और उन्होंने भी तपस्या की। फिर कृष्ण परमहंस के कहने पर इस मंदिर का निर्माण किया गया था। कहा जाता है कि इस मंदिर को बनने में लगभग 39 साल लग गए थे।

मंदिर में लगे पत्थरों को थपथपाने से एक आवाज आती है। ये आवाज डमरू जैसी सुनाई पड़ती है। लोगों का कहना है कि इस जगह पर भगवान शिव आकर रुके थे।

जटोली शिव मंदिर के पास एक जलकुंड भी है। साल 1950 में जब स्वामी कृष्णानंद परमहंस यहां आए थे, तब सोलन में पानी की कमी चल रही थी। ऐसे में स्वामी कृष्णानंद परमहंस ने घोर तपस्या की और फिर शिव ने अपने त्रिशूल से प्रहार कर इस जलकुंड का निर्माण किया था। कहते हैं कि त्रिशूल को जमीन पर मारते ही एक जलधारा फूट पड़ी। उसी से यहां पर जलकुंड तैयार हुआ। कहा जाता है कि इस जलकुंड में नहाने से रोगों से मुक्ति मिल जाती है।

कैसे पहुंचे मंदिर

मंदिर सोलन के चारों तरफ से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। ऐसे में यहां पहुंचने के लिए चंडीगढ़ तक ट्रेन या हवाई जहाज के जरिए पहुंचा सकते हैं। यहां से आप बस या टैक्सी करके सोलन जा सकते हैं।

ये हैं दिल्ली-एनसीआर की फेमस मस्जिदें, रमजान में करें इनका दीदार

रमजान के पाक महीने की शुरुआत 12 मार्च से हो गई है। इस महीने में मुस्लिम लोग रोजा रखते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। रोजा रखने के लिए सुबह सूर्योदय से पहले सेहरी खाते हैं, जिसके बाद तय समय पर रोजा शुरू हो जाता है। फिर शाम को इफ्तार के समय रोजा खोला जाता है। इस महीने में अल्लाह की इबादत करने के लिए दिल्ली की कुछ फेमस मस्जिदों में जा सकते हैं। दिल्ली में कई मस्जिद हैं और हर मस्जिद का अलग इतिहास है। ऐसे में आज हम आपको दिल्ली की कुछ फेमस मस्जिदों के बारे में बता रहे हैं। जानिए-

मोठ की मस्जिद

मोठ की मस्जिद साउथ दिल्ली में है और ये मस्जिद लगभग 500 साल पुरानी है। इसका निर्माण लोदी शासनकाल में वजीर मिया भोइया ने कराया था। यह मस्जिद खूबसूरती और ओनेखे इतिहास के लिए जानी जाती है। इस मस्जिद को बुर्ज इस्लामिक शैली के तर्ज पर डिजाइन किया गया हैं। सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक आप कभी भी इस मस्जिद का दौरा कर सकते हैं।

फतेहपुरी मस्जिद

ये मस्जिद पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित है। लाल पत्थरों से बनी ये मस्जिद देखने में बेहद खूबसूरत लगती है। 1877 के बाद भारत सरकार ने इस मस्जिद को अपने कब्जे में कर लिया। ईद-उल-फितर के दिन इस मस्जिद को शानदार तरीके से सजाया जाता है। इस दिन यहां हजारों की संख्या में लोग आते हैं। मुगल काल की कला से रूबरू होने के लिए यहां जरूर जाएं।

कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद

कुतुब मस्जिद के नाम से भी प्रसिद्ध इस मस्जिद का निर्माण गुलाम वंश के संस्थापक कुतुब-उद-दीन ऐबक ने शुरु करवाया था। एक और प्रमुख स्मारक है जो अभी भी दिल्ली के पुराने खंडहरों के बीच खड़ा है। यहां पहुंचने के लिए आप कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन उतरें और फिर आप मेट्रो से निकलने के बाद ऑटो ले सकते हैं।

जमाली कमाली मस्जिद

दिल्ली में कुतुब मीनार के ठीक बगल में जमाली कमाली मस्जिद है। यह मुगल काल इसे बलुआ पत्थर के एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है।

होली पर जरूर देखें वृंदावन के ये मंदिर, शानदार होता है यहां का नजारा

वृंदावन में होली एक महीने पहले से ही शुरू हो जाती है। रंगों की होली के अलावा यहां पर फूलों और लठ की होली भी बहुत फेमस है। यहां होली का जश्न देखने के लिए दुनियाभर से लोग आते हैं। इस दौरान विदेशी यात्री भी आपको यहां होली का जश्न मनाते दिख जाएंगे। इस साल होली सेलिब्रेशन के लिए अगर आप वृंदावन जा रहे हैं तो यहां हम आपका बता रहे हैं वृंदावन के उन मंदिरों के बारे में। जहां होली का जश्न देखने लायक होता है।

प्रेम मंदिर- वृंदावन के सबसे पवित्र और खूबसूरत मंदिरों में से एक है। जो भी लोग वृंदावन जाते हैं वह प्रेम मंदिर के दर्शन के लिए जरूर जाते हैं। सफेद संगमरमर के इस खूबसूरत मंदिर परिसर में भगवान कृष्ण के सभी रूपों को दिखाया गया है। यहां पर होली का जश्न देखने लायक होता है। ध्यान रखें कि होली पर यहां काफी भीड़ मिल सकती है।

बांके बिहारी मंदिर- बांके बिहारी मंदिर के अंदर हो खूब गुलाल और फूल उड़ाए जाते हैं। यहां पर रंग का पानी भी लोगों पर डाला जाता है। होली के दौरान वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर जरूर जाएं। इसी मंदिर के आसपास होली की सबसे ज्यादा रौनक होती है। मंदिर तक पहुंचने के लिए तंग गलियों से गुजरना पड़ता है और यहां से ही लोग होली खेलना शुरू कर देते हैं।

इस्कॉन मंदिर- इस्कॉन मंदिर में भी भक्तों की भीड़ लगी रहती है। यहां पर फूलों की होली होती है। यहां रंग बिरंगे फूलों की पंखुड़ियां हवा में दिखती है, ये नजारा बेहद खूबसूरत होता है।

गोविंद देव जी मंदिर- गोविंद देव जी मंदिर यहां के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। यहां भी होली बड़े ही धूम धाम के साथ मनाते हैं। होली पर आप इस जगह पर जा सकते हैं।

किसी नई जगह को करना चाहते हैं एक्सप्लोर तो जाएं इटावा

वैसे तो घूमने फिरने का शौक लगभग सभी को होता है। लेकिन किस जगह पर जाना है इसको लेकर सभी की अलग-अलग पसंद होती है। कई लोग नए शहरों की संस्कृति और खूबसूरती को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं तो वहीं कुछ लोग हमेशा कुछ चुनिंदा जगहों पर जाते हैं। अगर आप किसी नई जगह को एक्सप्लोर करने का सोच रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के इटावा शहरा को एक्सप्लोर करने के लिए जा सकते हैं। यहां जानिए इटावा की 5 बेहतरीन जगहों के बारे में- उत्तर प्रदेश के इटावा में स्थित इटावा सफारी पार्क एक वन्यजीव सफारी पार्क है जो पर्यटकों को खूब पसंद आता है। यह 8 किलोमीटर की परिधि के साथ एशिया के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। यह राज्य की राजधानी लखनऊ से लगभग तीन घंटे की ड्राइव पर है। पक्का तालाब इटावा के प्रमुख स्थलों में से एक है। यहां पर तालाब के साथ-साथ एक अद्भुत फव्वारा भी है। इस फव्वारे को चालू करने पर एक आश्चर्यजनक दृश्य सामने आता है। इस जगहों को देखने जरूर जाएं। इटावा शहर में कचौरा घाट एक बेहद आकर्षक जगह है। कचौरा घाट में पुराने किले के खंडहर देखे जा सकते हैं। किले में रख-रखाव की कमी के कारण यह किला पूरी तरह ढह गया, लेकिन फिर भी इसे देखने के लिए लोग पहुंचते हैं। श्री नीलकंठ मंदिर इटावा में एक प्रमुख हिंदू मंदिर है। यहां के स्थानीय लोग इस मंदिर को बहुत सम्मान देते हैं। यहां पर भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि जब पुजारी हर दिन मंदिर का दरवाजा खोलते हैं तो अंदर ताजे फूल उनका इंतजार कर रहे होते हैं। मंदिर में देवी की मूर्ति को सभी की इच्छाओं को पूरा करने वाली देवी के रूप में देखा जाता है। नवरात्रि के दौरान माता के दर्शन पाने के लिए लोग यहां जरूर जाते हैं।

बैंगलोर के पास प्रसिद्ध ये 5 हिल स्टेशन

इन दिनों पढ़ाई पूरी करने के बाद ज्यादातर यंगस्टर्स बैंगलोर पहुंच जाते हैं। खासकर वह लोग जो आईटी सेक्टर से हैं। समृद्ध संस्कृति, परंपरा, प्राकृतिक सुंदरता और नाइटलाइफ के लिए फेमस बैंगलोर लोगों की फेवरिट प्लेस बन रही है। यहां घूमने के लिए काफी जगह है। हालांकि, इसके आसपास मौजूद हिल स्टेशन को देखना लोग काफी पसंद करते हैं। हाल ही में होली पर लॉन्ग वीकेंड मिल रहा है, ऐसे में आप यहां के हिल स्टेशन को एक्स प्लोर करने के लिए जा सकते हैं। देखिए, बैंगलोर के पास फेमस हिल स्टेशन-

स्कंदगिरि हिल्स

स्कंदगिरी हिल्स ट्रैकिंग करने वालों के बीच काफी फेमस है। बेंगलुरु से 62 किलोमीटर दूर, स्कंदगिरी हिल्स घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी का है। यहां पापागनी मंदिर और टीपू सुल्तान का किला मुख्य आकर्षण का केंद्र है।

नंदी हिल्स

बैंगलोर के सबसे नजदीक और फेमस हिल स्टेशनों में से एक है नंदी हिल्स। सुंदर सूर्योदय, शानदार मौसम के कारण वीकेंड पर लोग यहां जाना पसंद करते हैं। यहां घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से जून का है। टीपू सुल्तान का ग्रीष्मकालीन महल नंदी हिल्स की चोटी पर है और यह बेंगलुरुवासियों के लिए सबसे अच्छे वीकेंड डेस्टिनेशन में से एक है।

अंतरगंगे

इस जगह पर चट्टानों से बनी कुछ आकर्षक गुफाएं हैं और साहसिक एक्टिविटी चाहने वालों के लिए ये एक आदर्श जगह है। यहां ट्रैकिंग, रॉक क्लाइम्बिंग और गुफाओं में जा सकते हैं। यहां पर कुछ पुराने मंदिर है और पहाड़ी पर कुछ प्राकृतिक झरने भी देखने लायक हैं।

शिवगंगा

पहाड़ी की चोटी तक जाने के रास्ते में कई पानी के स्थान हैं और वहां के लोगों का मानना ??है कि यह पानी पवित्र नदी गंगा का है। यही वजह है कि इस पहाड़ी का नाम शिवगंगा पड़ गया। इस जगह को आध्यात्मिक आकर्षणों के लिए भी जाना जाता है।

मेलागिरि

गर्मियों के दौरान बैंगलोर के पास घूमने के लिए सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है मेलागिरि। यहां पूरे साल पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। यहां होगेनक्कल झरना देखें, ये दुनिया के सबसे पुराने झरनों में से हैं।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

सीटों को लेकर राहुल और लालू की पार्टी के बीच ठन गई!

पटना। बिहार में इंडिया गठबंधन में दरार की खबरें सामने आ रही हैं। कांग्रेस की तरफ से 15 सीटों पर दावा किया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस से दावेदारी का आधार पूछ लिया। जिस पर कांग्रेस ने जवाब में कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पार्टी और मजबूत हुई है। 2019 में कांग्रेस ने बिहार में 9 सीटों पर लोकसभा के उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि उसके संसद पहुंचने का सिलसिला बेहद कमजोर रहा था। अब इस मामले को लेकर दोनों ओर से दावे अलग-अलग नजर आ रहे हैं। कांग्रेस अपने 15 सीटों पर दावेदारी के आधार को लेकर कह रही है कि 2019 के चुनाव में उसे तो एक सीट पर जीत हासिल हुई थी। लेकिन राजद का तो खाता भी नहीं खुला था। इसके बावजूद भी राजद 25 सीटों पर अपनी दावेदारी जता रही है। ऐसे में कांग्रेस को अगर 15 सीटें मिलती है और पार्टी का जनाधार बड़ा है।

पवन सिंह भाजपा के टिकट पर आसनसोल से लड़ेंगे चुनाव

कोलकाता। भोजपुरी गायक पवन सिंह ने ट्वीट में कहा कि भाजपा के आसनसोल उम्मीदवार के रूप में समर्थन वापस लेने के एक सप्ताह बाद चुनाव लड़ेंगे। भोजपुरी अभिनेता-गायक पवन सिंह ने अपने गानों को लेकर टीएमसी के हमलों का सामना करने के बाद आसनसोल से अपनी भाजपा उम्मीदवारी वापस ले ली। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से भाजपा की उम्मीदवारी वापस लेने वाले भोजपुरी अभिनेता-गायक पवन सिंह ने बुधवार को यू-टर्न लेते हुए कहा कि वह लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। पवन सिंह ने लिखा, मैं अपने समाज जनता जनार्दन और मां से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए चुनाव लडूंगा। आप सभी का आशीर्वाद एवं सहयोग अपेक्षित है। जय माता दी। भोजपुरी अभिनेता, जो भाजपा द्वारा घोषित 195 उम्मीदवारों की पहली सूची में शामिल थे, ने एक एक्स पोस्ट में कहा था, मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।

केरल में सीएए के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धरना

तिरुवनंतपुरम। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू होने से इसके कारण पड़ने वाले असर को भांपते हुए विपक्षी दलों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु ने साफ कर दिया है कि वे इस कानून को अपने राज्यों में लागू नहीं होने देंगे। वहीं, केरल में भी सीएए को लेकर हंगामा मचा हुआ है। यहां राजभवन के सामने बुधवार को केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने धरना दिया। केरल में सीएए लागू नहीं होने वाली अटकलों पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, राजनैतिक कारणों से कहा जा रहा है। मैं राजनीति के बारे में बात नहीं करना चाहूंगा। उन्होंने कहा, मैं बस यही कहूंगा कि सीएए के बारे में महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक हर किसी ने बात की है। यह वादा सन् 1947 में किया गया था। वहीं, राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने सांप्रदायिक आधार पर लोगों को बांटने के लिए सीएए लागू किया है।

हावड़ा से प्रसून बनर्जी को टिकट मिलने पर ममता के भाई नाराज

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की हावड़ा लोकसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के प्रसून बनर्जी को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी के इस फैसले से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के छोटे भाई बाबुन बनर्जी ने नाराजगी जताई है। बाबुन बनर्जी वर्तमान में दिल्ली में मौजूद हैं। उन्होंने फिलहाल भाजपा में शामिल होने वाले अटकलों को नकार दिया है। सीएम ममता बनर्जी के छोटे भाई ने बताया कि वह हावड़ा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, हावड़ा लोकसभा सीट से उम्मीदवार के चयन पर मैं खुश नहीं हूं। प्रसून बनर्जी सही विकल्प नहीं हैं। कई ऐसे योग्य उम्मीदवार हैं, जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा, मैं प्रसून द्वारा किए गए अपमान को कभी नहीं भूल पाऊंगा। बता दें कि प्रसून बनर्जी हावड़ा सीट से टीएमसी की तरफ से दो बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं।

परिस्थितियां बदलती रहती हैं लेकिन मैं भाजपा का भक्त हूं

चंडीगढ़। हरियाणा में सत्ता परिवर्तन के बाद से कथिततौर पर नाराज चल रहे पूर्व गृहमंत्री अनिल विज ने बुधवार को कहा कि राजनीति में परिस्थितियां बदलती रहती हैं और बदले हालात में भी वो भाजपा के भक्त हैं। इसलिए पार्टी के लिए काम करना जारी रखेंगे। सूत्रों के अनुसार अनिल विज बीते मंगलवार को पार्टी आलाकमान द्वारा मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाये जाने और उनकी जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने से आहत थे। कहा जा रहा है कि उसी कारण से अनिल विज बीते मंलवार शाम में राजभवन में नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और अन्य मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए। अनिल विज ने सूबे में हुई नये मुख्यमंत्री की ताजपोशी पर कहा, मैं भाजपा का भक्त हूं। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन मैंने हर परिस्थिति में पार्टी के लिए काम किया है। मैं आज भी काम करूंगा और ज्यादा ताकत से करूंगा। स्थितियाँ बदल सकती हैं लेकिन मैं पार्टी के लिए काम करना जारी रखूंगा।

क्या कांग्रेस को लगेगा एक और झटका?

उद्धव से क्यों नाराज हुए संजय निरुपम

मुंबई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के महाराष्ट्र आते ही कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री पद्माकर वलवी ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा, क्या इसके बाद कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगेगा? ऐसी चर्चाएं तब शुरू हो गई हैं जब संजय निरुपम ने अशोक चव्हाण से मुलाकात की है। उद्धव ठाकरे द्वारा अमोल कीर्तिकर को मुंबई उत्तर-पश्चिम लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित करने के बाद संजय निरुपम नाराज हैं। संजय निरुपम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी नाराजगी जाहिर की है। लेकिन अब खबर है कि संजय निरुपम ने अपने पुराने सहयोगी और बीजेपी सांसद अशोक चव्हाण से मुलाकात की है। इस दौरे से राजनीतिक गलियारों में चर्चा छिड़ गई है।

संजय निरुपम ने मंगलवार रात अशोक चव्हाण से उनके आवास पर मुलाकात की है। हालाँकि बातचीत का विवरण अभी भी गुप्त है, अगर संजय निरुपम ने कोई अलग निर्णय लिया, तो महाविकास अघाड़ी को नुकसान हो सकता है। मीडिया से बात करते हुए निरुपम ने बताया कि उन्होंने पार्टी के पूर्व सहयोगी से मुलाकात की। उन्होंने कहा, मैं किसी काम से दक्षिण मुंबई गया था और वहां मैंने अशोक चव्हाण को मुलाकात करने के लिए बुलाया था। वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं उनसे सिर्फ इसलिए मिलना बंद नहीं कर सकता कि वह दूसरी पार्टी के नेता हैं। निरुपम ने आगे बताया कि उन्होंने चाय पी और राजनीति पर चर्चा भी की। इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर कोई विकास के लिए आ रहा है तो उनका स्वागत है। इस बीच अशोक चव्हाण ने संजय निरुपम के दौरे पर प्रतिक्रिया दी है। संजय निरुपम मेरे पुराने मित्र हैं, उनकी और मेरी मुलाकात कभी-कभी होती है। जनमत के मुताबिक लोगों का मूड बीजेपी के साथ है। कांग्रेस में अब भी व्यक्तिगत रिश्ते हैं। चव्हाण ने कहा कि पुराने नेता मिलते रहते हैं और जो आना चाहते हैं उनका स्वागत करते हैं। जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आएंगे तस्वीर साफ होती जाएगी। अशोक चव्हाण ने संकेतात्मक बयान दिया है कि कई जिलों में सुगबुगाहट चल रही है, इसलिए बहुत सारे लोग हमारे पास आएंगे।

उद्धव ठाकरे द्वारा अमोल कीर्तिकर की उम्मीदवारी की

घोषणा के बाद संजय निरुपम ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की। संजय निरुपम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उद्धव ठाकरे की शिवसेना से नाराजगी जताई। शिवसेना ने अंधेरी से उत्तर पश्चिम लोकसभा के लिए महा विकास अघाड़ी के उम्मीदवार की घोषणा की है। महाविकास अघाड़ी की दो दर्जन बैठकों के बाद भी सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका है। निरुपम ने कहा कि सीट आवंटन बैठकों में भाग लेने वाले मेरे कांग्रेस सहयोगियों ने मुझे बताया कि यह सीट उन 8-9 सीटों में से है, जिन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। फिर भी अगर शिवसेना उम्मीदवार घोषित कर रही है तो क्या यह गठबंधन धर्म का उल्लंघन नहीं है?

बारामती को लेकर भाजपा की सहयोगी पार्टी शिवसेना और एनसीपी में बढ़ा टकराव

महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर जारी चर्चा के बीच भाजपा की सहयोगी पार्टी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उपमुख्यमंत्री अजित पवार की एनसीपी में टकराव पैदा हो गया है। महाराष्ट्र की प्रतिष्ठित सीट कही जाने वाली बारामती पर शिंदे के करीबी विधायक विजय शिवतारे ने ताल ठोंक दी है। उन्होंने कहा है कि बारामती किसी की जागीर नहीं है। वह इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। इससे न केवल एनसीपी बल्कि भाजपा की भी टेंशन बढ़ गई है। बारामती परंपरागत तौर पर एनसीपी संस्थापक शरद पवार का गढ़ रहा है। उनकी बेटी सुप्रिया सुले इस सीट से सांसद हैं लेकिन एनसीपी के दो फाड़ होने के बाद पवार परिवार ही आमने-सामने हैं। शरद पवार की एनसीपी (एसपी) ने सुप्रिया सुले को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वहीं, उपमुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के इस सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा है। ऐसे में बारामती में ननद-भौजाई की लड़ाई होने की संभावना है। इस बीच बारामती लोकसभा क्षेत्र की पुरंदर से तीन बार विधायक और पूर्व मंत्री शिवसेना के विजय शिवतारे ने भी लोकसभा चुनाव लड़ने का एलान कर दिया है। बारामती लोकसभा में छह विधानसभा क्षेत्र दौंड, इंदापुर, बारामती, भोर, पुरंदर और खड़कवासला शामिल है। विजय शिवतारे क्षेत्र में बापू के नाम से मशहूर हैं और वे पवार परिवार के परंपरागत प्रतिद्वंदी माने जाते हैं। शिवतारे को लगता है कि पवार परिवार में विघटन का उन्हें फायदा मिल सकता है और वे पवार से अपना पुराना हिसाब चुकता कर सकते हैं। विजय शिवतारे का कहना है कि वह बारामती सीट पर निर्दलीय या नरेंद्र मोदी विचार मंच के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि दशकों से इस सीट पर एक परिवार का नियंत्रण है। उन्होंने सीधे तौर पर पवार परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक ही परिवार को कई दशक से इस सीट पर क्यों बने रहना चाहिए। जबकि उस परिवार ने बारामती के लिए कुछ नहीं किया है। शिवतारे के इस बयान से शिवसेना (शिंदे गुट) के नेता स्तब्ध हैं। वहीं, उपमुख्यमंत्री पवार ने सीटों का बंटवारा होने तक सभी को शांत रहने की नसीहत दी है। बारामती में चाचा-भतीजा यानि शरद पवार और अजित पवार की प्रतिष्ठा दांव पर है। ऐसे में शिवसेना विधायक विजय शिवतारे के चुनाव लड़ने के एलान पर अजित पवार की एनसीपी में हड़कंप मच गया है। इस पर एनसीपी ने भी शिंदे की शिवसेना को चुनौती दे दी है। अजित गुट के नेता ठाणे और कल्याण से सांसद रह चुके आनंद परांजपे ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को धमकी दी है कि विजय शिवतारे को कंट्रोल करो। यदि बारामती में खुराफात करेंगे, तो कल्याण में खेला हो जाएगा। एकनाथ शिंदे के पुत्र श्रीकांत शिंदे कल्याण से सांसद हैं।

कांग्रेस ने महिला वोटरों को दी 'नारी न्याय गारंटी'

नौकरियों में 50 फीसदी कोटा, 1 लाख रुपये नकद ट्रांसफर

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव का खुमार अब राजनीतिक दलों पर तेजी से हावी होने लगा है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी आजकल अपनी रैलियों में मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं, वहीं अब कांग्रेस ने भी गारंटी के लिए कमर कस ली है। जी हां, कांग्रेस ने कर्नाटक और तेलंगाना विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी महिला वोटरों को लुभाने के लिए 5 चुनावी गारंटी का वादा किया है।

सूत्रों के अनुसार महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को अपनी महत्वाकांक्षी नारी न्याय गारंटी की घोषणा की, जिसके तहत उसने गरीब परिवारों की महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने का वादा किया है। कांग्रेस ने नारी न्याय गारंटी के तहत पांच प्रमुख घोषणाओं की रूपरेखा तैयार की है। जिसके तहत महिलाओं से महालक्ष्मी, आधी आबादी पूरा हक, शक्ति का सम्मान, अधिकार मैत्री और सावित्रीबाई फुले छात्रावास का वादा किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक वीडियो संदेश में कहा, आधी आबादी पूरा हक के तहत कांग्रेस केंद्र सरकार के स्तर पर होने वाली आधी नई भर्तियों में महिलाओं को अधिकार देगी।

उन्होंने कहा, अगर हम 2024 में सत्ता में आते हैं तो शक्ति का सम्मान के तहत आंगनवाड़ी, आशा और मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं की मासिक आय में दोगुने का योगदान करेंगे। खड़गे ने कहा कि महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सशक्त बनाने के लिए कांग्रेस ने हर पंचायत में एक पैरालीगल पेशेवर नियुक्त करने की योजना बनाई है, जिसे कानूनी ढांचे को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने में महिलाओं को शिक्षित करने और सहायता करने का काम सौंपा जाएगा।

पांचवीं और अंतिम पहल का उद्देश्य कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और किफायती आवास

से जुड़ी हुई है। जिसके तहत प्रत्येक जिला मुख्यालय पर कामकाजी महिलाओं के लिए कम से कम एक सावित्रीबाई फुले छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि इससे पहले हमने सहभागी न्याय, किसान न्याय और युवा न्याय की घोषणा की थी और अब यह कहने की जरूरत नहीं है, हमारी गारंटी भाजपा की तरह खोखले वादे और कोरे बयान नहीं होते हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी का 1926 से लेकर अब तक यही रिकॉर्ड रहा है, जब हमारे विरोधी पैदा हो रहे थे, हम तब से घोषणापत्र बना रहे हैं, उन घोषणाओं को पूरा कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि महिलाएं कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद देंगी और लोकतंत्र के साथ संविधान को बचाने की इस लड़ाई में हमारे हाथ मजबूत करेंगी।

गौरतलब है कि मंगलवार को कांग्रेस प्रमुख खरगे ने आदिवासियों से जुड़े छह संकल्पों की घोषणा की थी। खरगे ने कहा था कि उनकी पार्टी जल-जंगल और जमीन को बचाने के लिए संकल्पित है। उन्होंने आदिवासी लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी के छह संकल्पों का भी जिक्र किया। सुशासन, सुधार, सुरक्षा, स्वशासन, स्वाभिमान और सब प्लान के रूप में पार्टी के संकल्पों का ब्यौरा भी पेश किया। खरगे ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर हैशटैग आदिवासी संकल्प का भी जिक्र किया।

खेल
प्रमुख समाचार

टेस्ट मैच में अश्विन विश्व के नंबर एक गेंदबाज बने

दुबई। आईसीसी ने बुधवार को टेस्ट की ताजा रैंकिंग जारी कर दी है। भारत के रविचंद्रन अश्विन दुनिया के नंबर एक गेंदबाज बन गए हैं। धर्मशाला में इंग्लैंड के खिलाफ अपने 100वें टेस्ट में नौ विकेट लेने के बाद वह एक पायदान ऊपर चढ़कर शीर्ष स्थान पर पहुंच गए। वहीं, जसप्रीत बुमराह लुढ़क कर तीसरे स्थान पर आ गए हैं। वहीं, भारत के कुलदीप यादव ने भी लंबी छलांग लगाई है। इसके अलावा बल्लेबाजों में रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को भी फायदा हुआ है।

37 साल के भारतीय दिग्गज स्पिनर ने धर्मशाला में टीम इंडिया की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने पहली पारी में चार और दूसरी पारी में पांच विकेट झटके थे। दोनों पारियों को मिलाकर अश्विन ने 128 रन देकर नौ विकेट झटके थे। अश्विन ने बुमराह को शीर्ष स्थान से हटाया है। इससे पहले बुमराह भी अश्विन को हटाकर नंबर एक टेस्ट गेंदबाज बने थे। अश्विन के 870 रेटिंग पॉइंट्स हैं। वहीं, दूसरे नंबर पर 847 रेटिंग पॉइंट्स के साथ ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड और तीसरे नंबर पर जसप्रीत बुमराह हैं। कगिसो रबाडा चौथे और पैट कमिंस पांचवें स्थान पर हैं। शीर्ष 10 गेंदबाजों में भारत के रवींद्र जडेजा सातवें स्थान पर बने हुए हैं। वहीं, शीर्ष 20 में कुलदीप यादव की एंट्री हुई है। उन्होंने 15 पायदान की छलांग लगाई और 16वें स्थान पर पहुंच गए। शीर्ष-20 गेंदबाजों में भारत के चार गेंदबाज हैं।

वहीं, टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में धर्मशाला में शतक लगाने वाले रोहित शर्मा और शुभमन गिल को भी फायदा हुआ है। रोहित ने पांच स्थान की छलांग लगाई और वह छठे स्थान पर पहुंच गए। वहीं, यशस्वी जायसवाल भी दो स्थान की सुधार के साथ आठवें पायदान पर पहुंच गए। विराट कोहली को एक स्थान का नुकसान हुआ है और वह नौवें स्थान पर लुढ़क गए हैं।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 906 अंक टूटा निफ्टी 22 हजार के नीचे

नई दिल्ली। स्मॉलकैप और मिडकैप सूचकांकों में भारी गिरावट और व्यापक बिकवाली दबाव के बीच हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को सेंसेक्स 900 अंक से ज्यादा टूटकर 73,000 के स्तर से नीचे आ गया। दलाल स्ट्रीट पर बिकवालों के हावी रहने से निवेशक 13.5 लाख करोड़ रुपये के नुकसान में चले गए। आज के कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 906 अंक कमजोर हुआ। वहीं, निफ्टी में भी 338 अंक की गिरावट दर्ज की गई। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 906.07 अंक यानी 1.23 फीसदी की भारी गिरावट के साथ 72,761.89 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज 72,515.71 और 74,052.75 के रेंज में कारोबार हुआ। वहीं, दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी 338 अंक यानी 1.51 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी दिन के अंत में 21,997.70 अंक पर बंद हुआ।

ग्लोबल ट्रेड में 2024 में तेजी आने की उम्मीद : रिपोर्ट

नई दिल्ली। कोविड-19 महामारी, यूक्रेन और गाजा में युद्ध और अमेरिका-चीन व्यापार विवाद के बीच वैश्वीकरण 2022 में पिछले दशक की तुलना में रिकॉर्ड उच्चस्तर पर पहुंच गया और 2023 में भी यह ऊंचे स्तर पर बना हुआ है। एक रिपोर्ट में बुधवार को यह बात कही गई है। डीएचएल और न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस द्वारा यहां जारी 'न्यू डीएचएल ग्लोबल कनेक्टेडनेस रिपोर्ट-2024' में यह भी कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार वाले वैश्विक उत्पादन का हिस्सा 2022 में रिकॉर्ड उच्चस्तर पर फिर वापस आ गया है।इसमें कहा गया है कि 2023 में सुस्ती के बाद 2024 में व्यापार वृद्धि में तेजी आने का अनुमान है। व्यापार वृद्धि ने संपर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रिपोर्ट में व्यापार के प्रवाह, पूंजी, सूचना और लोगों की आवाजाही का आकलन किया गया है।

भारत के लिए सिंगापुर से अधिक निवेश लाने को प्रतिबद्ध

नईदिल्ली। भारतीय उच्चायोग सिंगापुर से भारत में अधिक से अधिक निवेश के लिए काम कर रहा है। भारतीय उच्चायुक्त शिल्पक अंबुले ने यह बात कही है। अंबुले ने कहा कि भारत के बुनियादी ढांचा, नवीकरणीय ऊर्जा और आधुनिक प्रौद्योगिकी क्षेत्र ने आक्रामक तरीके से प्रगति की है, ऐसे में हम भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक निवेश लाने का प्रयास कर रहे हैं। उच्चायुक्त ने वृद्धि को गति देने वाले तीन कारकों का उल्लेख करते हुए कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के साथ भारत के लिए यह हरित वृद्धि होगी। इसके अलावा आर्थिक गतिविधियों के सुगम प्रवाह के लिए डिजिटल ढांचा बनाया गया है। साथ ही भारत की सतत वृद्धि भी एक कारक है जिसकी वजह से उसे निवेश मिलेगा। उच्चायुक्त ने मंगलवार शाम यहां '2024 बजट विश्लेषण- सिंगापुर और भारत' कार्यक्रम में कहा, ''हम सिंगापुर से भारत में अधिक निवेश लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।''

भारत डेकाथलॉन के पांच टॉप बाजारों में होगा : अधिकारी

नईदिल्ली। फ्रांस की खेल क्षेत्र की रिटेलर डेकाथलॉन के लिए भारत एक 'बड़ी प्राथमिकता' वाला बाजार है। कंपनी को भरोसा है कि स्टोर नेटवर्क के विस्तार और स्थानीय सोर्सिंग में बढ़ोतरी के साथ अगले पांच साल में भारत उसके शीर्ष पांच वैश्विक बाजारों में शामिल होगा। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने यह बात कही है। कंपनी के मुख्य रिटेल एंड कंट्रीज ऑफिसर स्टीव डाइक्स ने कहा कि डेकाथलॉन अपनी वृद्धि की योजनाओं के तहत भारत में हर साल 10 नए स्टोर खोलेगी। साथ ही कंपनी का इरादा ऑनलाइन बिक्री में तेजी लाने और अगले पांच साल में स्थानीय सोर्सिंग को मौजूदा के औसतन 60 प्रतिशत बढ़ाकर 90 प्रतिशत करने का है। उन्होंने कहा कि इस कदम से डेकाथलॉन को तेजी से बढ़ते भारतीय खेल और 'एथलेजर' खंड में अधिक प्रतिस्पर्धी बनने में मदद मिलेगी।

नये मुक्त व्यापार समझौते की अहमियत

डॉ. जयंतीलाल

10 मार्च को भारत और चार यूरोपीय देशों के समूह यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (इएफटीए) ने निवेश और वस्तुओं एवं सेवाओं के दोतरफा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर किये हैं। इसे व्यापार और आर्थिक समझौता (टीइपीए) कहा गया है। एफटीए के तहत ईएफटीए ने अगले 15 साल में भारत में 100 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जतायी है। यह भारत का ऐसे समूह के साथ पहला व्यापार करार है, जिसमें विकसित देश शामिल हैं। इएफटीए के सदस्य देशों में आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और लिकटेंस्टाइन शामिल हैं। समझौते के 14 अध्यायों में वस्तुओं के व्यापार, उत्पत्ति के नियम, शोध एवं नवाचार, बौद्धिक संपदा अधिकार (आइपीआर), सेवाओं का व्यापार, निवेश प्रोत्साहन और सहयोग, सरकारी खरीद, व्यापार में तकनीकी बाधाएं और व्यापार सुविधा शामिल है। इससे भारत में 10 लाख प्रत्यक्ष नौकरियां निर्मित होंगी। इस समझौते में निवेश पर अधिक जोर दिया गया है।

इन चार यूरोपीय देशों से होने वाले भारत के कुल व्यापार में स्विट्जरलैंड की हिस्सेदारी 90 प्रतिशत से अधिक है। समझौते से डिजिटल व्यापार, बैंकिंग, वित्तीय सेवा, फार्मा, टेक्सटाइल जैसे सेक्टर में इन देशों के बाजार में भारत की पहुंच आसान होगी। बदले में भारत इन देशों की विभिन्न वस्तुओं के लिए आयात शुल्क कम करेगा। कृषि, डेयरी, सोया व कोयला सेक्टर को इस व्यापार समझौते से दूर रखा गया है, साथ ही पीएलआई स्कीम से जुड़े सेक्टर के लिए भी भारतीय बाजार को नहीं खोला गया है। यह भी महत्वपूर्ण है कि ग्रीन व विंड एनर्जी,

फार्मा, फूड प्रोसेसिंग, केमिकल्स के साथ उच्च गुणवत्ता वाली मशीनरी के क्षेत्र में ईएफटीए देश भारत में निवेश करेंगे, जिससे इन सेक्टर में हमारा आयात भी कम होगा और भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद भी मिलेगी। समझौते में स्विट्जरलैंड के शामिल होने से भारत में लोकप्रिय उसके चॉकलेट, घड़ी व बिस्कुट कम कीमत पर मिलेंगे। समझौते के मुताबिक इन वस्तुओं पर वर्तमान आयात शुल्क को अगले सात साल में चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। हर साल शुल्क में थोड़ी-थोड़ी कटौती होती रहेगी। इस समझौते से इएफटीए देशों को वृद्धि के लिए भारत के बड़े बाजार तक पहुंच मिली है।

भारतीय कंपनियां भी अपनी आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने का प्रयास करेंगी। भारत और इएफटीए देश समझौते पर 15 साल से भी अधिक समय से बातचीत कर रहे थे। साल 2013 के अंत में वार्ता रुक गयी थी। साल 2016 में बातचीत फिर शुरू हुई और अब यह समझौता धरातल पर आया है। यह व्यापार समझौता मुक्त, निष्पक्ष और समानता वाले व्यापार के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इसके जरिये भारत और इएफटीए देश आर्थिक रूप से परस्पर पूरक बन जायेंगे। ज्ञातव्य है कि इएफटीए देश यूरोपीय संघ (इयू) का हिस्सा नहीं हैं। यह मुक्त व्यापार को बढ़ाया देने के लिए एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना उन देशों के लिए एक विकल्प के रूप में हुई थी, जो यूरोपीय समुदाय में शामिल नहीं होना चाहते थे। इस समय भारत वैश्विक नेतृत्वकर्ता देश के रूप में उभरता दिख रहा है। ऐसे में कई विकसित और विकासशील देश भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए उत्सुक हैं। भारत सबसे तेज अर्थव्यवस्था के साथ विकास की डगर पर बढ़ रहा है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी, सबसे अधिक कौशल प्रशिक्षण के अभियान, बढ़ता सर्विस सेक्टर, बढ़ते निर्यात और अर्थव्यवस्था के बाहरी झटकों से उबरने की क्षमता नये भारत के निर्माण की बुनियाद बन सकती है। प्रवासी भारतीयों द्वारा प्रति वर्ष अधिक धन भेजने के साथ भारत को तकनीकी विकास के लिए मदद बढ़ी है। ये सारी बातें भारत के लिए नये एफटीए की नयी संभावनाओं की बड़ी आधार हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि मुक्त व्यापार समझौते भारत को निम्न मध्यम से उच्च मध्यम आय वाला देश बनाने में मददगार होंगे।

मुख्यमंत्री सचिव राहुल भगत को मिली सामान्य प्रशासन की जिम्मेदारी

रायपुर। लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश में आईएएस, आईपीएस अफसरों के तबादले और पोस्टिंग का दौर जारी हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री के सचिव आईपीएस राहुल भगत को सामान्य प्रशासन ने अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी हैं।

बदले गए अफसरों के प्रभार

आगामी दिनों लोकसभा चुनाव होने को है। हांलकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन इससे पहले छत्तीसगढ़ में तबादलों का दौर जारी है। आए दिन अलग अलग विभागों अधिकारियों के ट्रांसफर हो रहे हैं। इसी बीच एक बार फिर आधा दर्जन आईएएस अफसरों का ट्रांसफर आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के अनुसार दीपक सोनी, आयुक्त, मनरेगा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं कुलदीप शर्मा, नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन नियुक्त किया गया है। साथ ही अमृत टोपनो, कलेक्टर सक्ती की जिम्मेदारी दी गई है। इतना ही नहीं नूपुर राशि पन्ना, सीईओ राज्य जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी और नम्रता जैन, संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में नियुक्त किया गया है।

छग को मिले 4 नए आईएएस

रायपुर समेत इन चार जिलों में सहायक कलेक्टर के बतौर हुई पहली नियुक्ति

छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार ने चार नए आईएएस दिए हैं। मसूरी से ट्रेनिंग के बाद पहली नियुक्ति इनकी छत्तीसगढ़ में हुई है। जारी सूची के अनुसार अनुपमा आनंद, सहायक कलेक्टर रायपुर बनाए गए हैं। एम भार्गव, सहायक कलेक्टर दुर्ग, तन्मय खन्ना, सहायक कलेक्टर बिलासपुर और दुर्गा प्रसाद को सहायक कलेक्टर जांजगीर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ सीएमओ ने भी एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है। जिसमें लिखा है छत्तीसगढ़ को मिले चार नए आईएएस, राज्य शासन द्वारा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2023 बैच के 4 अधिकारियों के पदस्थापना आदेश जारी।

शिक्षा विभाग में कई प्राचार्य बनाए गए जिला शिक्षा अधिकारी

बीते दिन प्रशासनिक फेरबदल के बाद अब 25 से ज्यादा जिला शिक्षा अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। इस सूची में कई प्राचार्यों को जिला शिक्षा अधिकारी बना दिया गया है। छत्तीसगढ शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किया है।

छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए राज्य सरकार ने कई स्कूलों के प्राचार्य को जिला शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी दे दी है। शिक्षा विभाग में लोकसभा चुनाव से पहले हुए इस फेरबदल से पूरी तस्वीर ही बदल गई है।

वन विभाग में फेरबदल

आगामी दिनों लोकसभा चुनाव होने को हैं। लेकिन इससे पहले छत्तीसगढ़ में तबादलों का दौर जारी है। यहां लगातार अलग अलग विभागों से कई अधिकारियों के ट्रांसफर हो रहे हैं। इसी बीच एक बार फिर वन विभाग में बड़े पैमाने पर 5 अधिकारियों के तबादले हुए हैं। इस बाबत में वन विभाग ने आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के अनुसार, अभिनव कुमार को उप मंडलाधिकारी बिलासपुर भेजा गया है। वहीं अजय दिनक भोसले को उप मंडलाधिकारी कसडोल में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा हिमांशु डांगरे को उप मंडलाधिकारी राजिम भेजा गया है। नीरज को उप मंडलाधिकारी मनेंद्रगढ़ तो निखिल अग्रवाल को जशपुर उप मंडलाधिकारी नियुक्त किया गया है।

कलेक्टर-एसपी कांफ्रेंसः कलेक्टर-एसपी के कार्यो से ही सरकार की छवि बनती हैः मुख्यंत्री

संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ काम करें: साय

अन्नदाता किसानों को दफ्तरों का चक्कर न लगाना पड़े
बस्तर में सुरक्षा कैंप की छवि सुविधा कैंप के रूप होनी चाहिए

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कलेक्टर-एसपी कांफ्रेंस लेकर शासन की योजनाओ और कानून व्यवस्था को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज तीन महीने के बाद कलेक्टर-एसपी कांफ्रेस हो रही है। तीन महीने के भीतर ही निश्चित रूप से आप लोगो के सहयोग से हमारी सरकार ने जनता के विश्वास के मुताबिक बहुत से काम किये हैं और मोदी की गारंटी को पूरा किया है। हमें और भी अच्छा काम करने की जरूरत है। जनता ने हमें विश्वास से बैठाया है, हमें जनता के विश्वास के मुताबिक और अच्छा काम करना है। मोदी की गारंटी में विश्वास करके छत्तीसगढ़ की जनता ने हमको सरकार में बैठाया है, इस तीन महीने में हमने बहुत काम किया है, प्रधानमंत्री आवास योजना, बकाया धान का बोनस, धान की बम्पर खरीदी, 21 क्विंटल प्रति एकड़ 3100 की दर से, कल अंतर की राशि भी दे दिए। महतारी वंदन योजना के तहत पहली किश्त की राशि भी जारी हो गई है। एक तरह से 3 महीने में हमने बहुत काम किया है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य शासन और भारत सरकार की बहुत सारी योजना प्रदेश में संचालित है। सभी योजनाओं को प्रदेश की अंतिम व्यक्ति तक पहुचाने की आवश्यकता है, कलेक्टर ध्यान रखे कि जिला प्रशासन की तरफ से योजना पहुचाने में किसी भी तरह की कोताही न हो, ढिलाई बर्दास्त नहीं की जाएगी।

हमारे प्रधानमंत्री अपने आपको प्रधानमंत्री नही मानते वो भी अपने आपको जनसेवक ही मानते हैं। हम सब भी लोक सेवक हैं, हम सबका उद्देश्य जनसेवा है। कलेक्टर से लेकर पटवारी तक और एसपी से लेकर आरक्षक तक हम सबको जनता की सेवा में तत्पर रहना होगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राजस्व विभाग में कई तरह की शिकायत मिल रही हैं।

ग्रामीण स्तर में पटवारी, आरआई द्वारा बंटवारा, नामातंरण का काम ठीक से और त्वरित रूप से नही होने की शिकायत प्राप्त हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कामों को टालने की पुरानी व्यवस्था को तत्काल बदले। सभी कलेक्टर यह सुनिश्चित करें कि राजस्व विभाग से संबंधित शिकायत ना आने पाए। आम जनता को परेशानी का सामना न करना पड़े। जो भी आवश्यक दस्तावेज की जरूरत राजस्व विभाग के अधिकारियों से हो लोगों को तत्काल मिल जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 दिन का सप्ताह हो गया है, 5 दिन पूरे तन्मयता से कार्य हो। दफ्तरों में सभी समय पर उपस्थित हो जाये यह सुनिश्चित किया जाए।

पूरी पारदर्शिता के साथ प्रदेश सरकार और भारत सरकार की योजना लोगों तक पहुचे इस ओर जिला प्रशासन ध्यान दे। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि अपने प्रदेश में सुशासन देंगे। इस पर भी आप लोग विशेष ध्यान दे। हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी विकसित भारत की बात करते हैं, हमें भी विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित जिला बनाने की आवश्यकता है, उसी के अनुरूप कार्य हों।

कलेक्टर-एसपी के कार्य से ही सरकार की छवि बनती है। जिला प्रशासन के अच्छे कार्य से ही जनता आप लोगों की तारीफ हमसे करती है। आप लोगों की तारीफ जनता से हमे प्राप्त होने चाहिए। हमारे किसान अन्नदाता है और छत्तीसगढ़ में ज्यादातर किसान ही है। जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि किसानों को दफ्तरों का चक्कर न लगाना पड़े। किसानों का कार्य समयावधि में पूरा हो यह सुनिश्चित किया जाए।

डीएमएफ फंड में भारी भ्रष्टाचार पिछली सरकार में हुआ है। डीएमएफ फंड की राशि खनन प्रभावित क्षेत्र के विकास के लिए होती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सड़क और आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए यह राशि खर्च की जाए। डीएमएफ की राशि की उपयोग के लिए भारत सरकार से नियम तय है, नियमानुसार ही यह राशि खर्च हो। इस पर सख्ती से ध्यान दिया जाए, इस राशि का बिल्कुल भी दुरुपयोग नही होना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर में नल के माध्यम से पानी पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए इन कार्यो को योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण कराया जाए। सबसे पहले जल स्त्रोतों का पता लगाया जाए, इसके बाद टंकी बनाने, पाइप लाइन बिछाने का काम किया जाए। जलजीवन मिशन योजना से लोगों को लाभ हो, पेयजल मिले यह सुनिश्चित हो। कार्य एजेंसी और ठेकेदार पर निगरानी हो ताकि सही कार्य हो सके।

तेंदूपत्ता खरीदी का समय आ गया है, शासन द्वारा प्रति मानक बोरा 5500 की दर निर्धारित की गई है। यह ध्यान रखें कि तेंदूपत्ता संग्रहकों समय पर पारिश्रमिक भुगतान तथा उनके उनके लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिले। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के कार्य ठीक से चलें और समय पर भुगतान हो। मजदूरी के लिए मजदूरों को भटकना न पड़े। जितने भी स्वीकृत कार्य है, समय पर कार्य प्रारंभ हो और पूरा हो यह भी सुनिश्चित की जाएं।

बृजमोहन ने दी अपने विभागों के 3 माह की प्रोग्रेस रिपोर्ट

पांच साल बाद फिर से लौटी राजिम कुंभ की भव्यता, विवि और महावि. में 4200 से अधिक रिक्त पदों पर जल्द होगी भर्ती

रायपुर. साय सरकार के तीन माह पूरे होने पर शिक्षा एवं संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने अपने विभागों के 3 महीनों की प्रोग्रेस रिपोर्ट की जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 3 माह के अल्प समय में ही कई बड़े फैसले और दूरगामी निर्णय लिए हैं. आने वाले समय में विकसित भारत की संकल्पना को पूर्ण करने के लिए छत्तीसगढ़ में भी तैयारियां की जा रही है. विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, धर्मस्व, पर्यटन एंव संस्कृति विभाग की गतिविधियां तय की गई है. संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि विकसित छत्तीसगढ़ बनाने राज्य में नई शिक्षा नीति को लागू करने जा रहे हैं. स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के अधोसरंचना को मजबूत कर रहे हैं. स्कूल अधोसरंचना को मजबूत करने के लिए बजट में 265 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है. सनातन संस्कृति के प्रति गौरव का भाव जगाने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए त्रिवेणी संगम भव्य राजिम कुम्भ का फिर से आयोजन की शुरूआत की है. जनभावना का सम्मान करते हुए श्री रामलला दर्शन योजना की शुरूआत की है. 5 मार्च को 850 लोगों का जत्था विशेष ट्रेन से अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई है. इस पूरी यात्रा का खर्च राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी अयोध्या धाम के भव्य रामलला मंदिर की तर्ज पर नवा रायपुर स्थित मुक्तांगन में अयोध्या धाम का प्रतिरूप बनाया जाएगा. अग्रवाल ने कहा, वनांचल क्षेत्रों में भी आदिम संस्कृति के गौरव प्रदान करने के लिए बस्तर दशहरा के आयोजन के लिए राशि बढ़ाकर प्रत्येक वर्ष 50 लाख रुपए, चित्रकोट महोत्सव के लिए 25 लाख रुपए और रामाराम महोत्सव के लिए 15 लाख रुपए, गोंचा महोत्सव के लिए धनराशि 5 लाख रुपए कर दी गई है. मानसरोवर यात्रा और सिंधु दर्शन यात्रा के लिए भी आर्थिक सहायता राशि को बढ़ाकर राशि को 50 हजार रूपए प्रति यात्री किया गया है. संस्कृति मंत्री ने बताया, छत्तीसगढ़ सरकार चार धाम के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में पांच शक्तिपीठों विकसित करेगी. इसके अंतर्गत कुदरगढ़ जिला सूरजपुर, चंद्रहासिनी चन्द्रपुर जिला-सक्ती, महामाया रतनपुर जिला-बिलासपुर, दंतेश्वरी जिला दंतेवाड़ा और बम्लेशवरी डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव को चारधाम की तर्ज पर विकसित करने के लिए योजना तैयार की जा रही है. इस योजना की लागत 112 करोड़ की होगी. इस वर्ष बजट में 5 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है.

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली सरकार को तीन महीने पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के साथ ही मंत्रिगणों और आम नागरिकों ने मुख्यमंत्री साय को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री साय भी लोगों से आत्मीयता से मिले, उनका अभिवादन स्वीकारा और आगे भी प्रदेश के विकास के लिए शासन-प्रशासन के सहयोग का आग्रह किया। इस मौके पर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय भी मौजूद रहीं।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने साव ने दिए निर्देश

रायपुर। उप मुख्यमंत्री एवं बेमेतरा जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने बेमेतरा कलेक्टोरेट में अधिकारियों की बैठक लेकर सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक प्राथमिकता से पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को नई ऊर्जा और उत्साह के साथ काम करते हुए अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारीपूर्वक निर्वहन करने को कहा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बैठक में कहा कि बदलते समय के अनुरूप जिले में विकास कार्यों को गति देने के लिए सभी अधिकारी नई सोच के साथ काम करें। कार्य को पूर्ण करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर दक्षता के साथ टीम के रूप में कार्य करें। उन्होंने अधिकारियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि आप सभी अपने कर्तव्यों का इस प्रकार निर्वहन करें कि आपके कार्यों से आपकी पहचान और प्रतिष्ठा बढ़े। इससे सरकार पर भी लोगों का भरोसा बढ़ेगा। उप मुख्यमंत्री साव ने विभागीय योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को नियमित रूप से फील्ड में जाकर मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के फील्ड में जाने से कार्यों में गति आती है. और उन्हें योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत पता चलती है।

आयुर्वेद पूरे विश्व को हमारी देनः बृजमोहन अग्रवाल

रायपुर। शिक्षा पर्यटन एवम संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल रायगढ़ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ऑफ आयुर्वेदा एवं रुद्राक्ष वेलनेस रिसोर्ट का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस संस्थान के माध्यम से रायगढ़ में अब आयुर्वेद और पंचकर्म पद्धति की चिकित्सा सुविधाएं लोगों को मिलेगी। ऐसा वेलनेस सेंटर बड़े शहरों में देखने को मिलता है अब यह रायगढ़ में खुला है तो इसका लाभ यहां के साथ आस-पास के लोगों को मिलेगा। शिक्षा मंत्री अग्रवाल ने कहा कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति हमारे देश द्वारा पूरे विश्व को दी गई एक अनुपम सौगात है। इसे पूरी दुनिया अपना रही है। हमारे देश के आयुर्वेदिक चिकित्सा सेंटर्स में दूसरे देशों से लोग आ रहे हैं। उन्होने कहा कि आयुर्वेद में प्राकृतिक औषधियों का उपयोग रोगों के उपचार में किया जाता है। समय के साथ धीरे-धीरे लोग त्वरित राहत के लिए इलाज के दूसरे तरीकों की ओर जाने लगे और आयुर्वेद उतना प्रचलन में नही रहा। किंतु आज समय बदल रहा है, लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति पहले से ज्यादा सजग हो रहे हैं। प्रसन्नता की बात है कि युवा वर्ग भी अब अपने खान-पान और व्यायाम की आदतों में प्राकृतिक पद्धतियों का समावेश कर रहे हैं। मंत्री अग्रवाल ने कहा कि यदि हम प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति, खान-पान और जीवन शैली को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा स्वास्थ्य लंबे समय तक अच्छा बना रहेगा।

गृहमंत्री शर्मा ने राजनांदगांव में कार्यकर्ताओं की बैठक ली

राजनांदगांव. छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री एवं राजनांदगांव जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा आज राजनंदगांव पहुंचे. यहां उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक ली. वहीं कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रशासनिक योजनाओं की समीक्षा करने अफसरों की बैठक भी ली. उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने राजनांदगांव के जिला भाजपा कार्यालय में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न मोर्चा के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को चार्ज किया. उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनांदगांव लोकसभा से चुनाव लड़ने के मामले को लेकर कहा कि भूपेश बघेल अपने दुर्ग क्षेत्र से भाग कर राजनांदगांव में चुनाव लड़ रहे हैं. भाजपा आईटी सेल द्वारा कांग्रेस के खिलाफ कार्टूनवार को लेकर मंत्री शर्मा ने कहा कि कार्टून पुरानी घटनाओं के आधार पर कल्पना के तहत बनाया गया है. वहीं सीएए के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि यह नागरिकता देने का बिल है. इसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी. इस बिल का स्वागत होना चाहिए.

पॉवर कंपनी में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर संयुक्त मोर्चा खोला

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी में अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने एक बार फिर पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पावर कंपनी मुख्यालय में आयोजित आमसभा में अधिकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना संयुक्त मोर्चा ने आम सभा कर कंपनी प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा। मोर्चा का कहना है कि राज्य शासन के आदेश अनुसार पावर कंपनी में वर्ष 2004 से नियुक्त सभी कर्मचारियों अधिकारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल किया जाए । इस हेतु राज्य शासन ने पहले ही 06 अक्टूबर 23 को आदेश जारी किया था जिस पर कंपनी प्रबंधन को सिर्फ मुहर लगाना बाकी है। इस सिलसिले में आज संयुक्त मोर्चा द्वारा आयोजित आमसभा में सैकड़ों अधिकारियों कर्मचारियों ने हिस्सा लिया और अपनी मांगों के समर्थन में प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा। संयुक्त मोर्चा में शामिल विभिन्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संगठनों के प्रतिनिधियों ने राज्य शासन के कैबिनेट के अनुमोदन एवं ऊर्जा विभाग द्वारा दिनांक 6 अक्टूबर 2023 के आदेश का परिपालन जल्द नहीं किए जाने पर पूर्व की भांति सामूहिक हड़ताल समेत धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है।

साय सरकार बनने के बाद लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि साय की सरकार बनने के बाद प्रदेश में लोकतंत्र का गला घोट जा रहा है. कवर्धा में बिना बहुमत के अपने अध्यक्ष का मनोनयन कर दिया तथा कांग्रेस पार्षद की सहमति के बिना पीआईसी का सदस्य बना दिया, जिसके खिलाफ में कांग्रेसी पार्षदों ने सीएमओ का घेराव भी किया। कवर्धा की जनता ने पालिका में कांग्रेस को 18 पार्षद के साथ बहुमत दिया है भरोसा किया है और भाजपा को 6 पार्षद देकर विपक्ष के लायक बनाया है. भाजपा जो आदतन लोकतंत्र की विरोधी है उसने सरकारी तंत्रो का दुरुपयोग करके पालिका की बहुमत के खिलाफ जाकर कवर्धा पालिका के अध्यक्ष पद पर अतिक्रमण किया है. और जोर जबरदस्ती कांग्रेस के पार्षद को बिना सहमति के सभापति बनाया है भाजपा का यह कृत्य बेहद निंदनीय हैं और तानाशाही हैं। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद लोकतंत्र की चुनी हुई परिषदों को तोड़फोड़ कर हटाया जा रहा है, कई बार भाजपा के नेताओं ने सामाजिक तौर पर कहा है की पंचायत स्तर पर चुनाव नहीं होना चाहिए यानी लोकतंत्र के अधिकारों को वह छीनना चाहते हैं और मनोनयन करने की बात करके वह डिक्टेटरशिप स्थापित करना चाहते हैं.

लोस चुनावः प्रचार के लिए छापे गये पाम्पलेट-पोस्टरों की जानकारी 72 घंटे के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी को देंगे मुद्रक

पोस्टर-पाम्पलेट में प्रकाशक-मुद्रक का नाम और संख्या नहीं छापने पर होगी कार्यवाही

रायपुर। आगामी लोकसभा निर्वाचन-2024 की तैयारियों के संबंध में आज कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर जिले के विभिन्न प्रिंटरों और प्रकाशकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की गई। रेडक्रॉस सभाकक्ष में आयोजित इस बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमाशंकर बन्दे और मास्टर ट्रेनरों ने प्रिंटरों और मुद्रकों को लोकसभा निर्वाचन के दौरान छापी जाने वाली राजनैतिक प्रचार-प्रसार सामग्रियों के बारे में निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी। श्री बन्दे ने बैठक में कहा कि विधानसभा निर्वाचन के लिए आदर्श आचार

संहिता प्रभावशील होते ही सभी प्रिंटरों-मुद्रकों और प्रकाशकों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में निहित प्रावधानों और दिशा-निर्देशों का पालन करना बंधनकारी होगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मुद्रकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वह निर्वाचन के दौरान प्रचार के लिए छापी गई सामग्री की तीन प्रतियां और प्रकाशक की घोषणा जिला निर्वाचन कार्यालय में छपाई के 72 घंटे या तीन दिन के भीतर जमा करायें। उन्होंने कहा कि मुद्रित की गई सामग्रियों पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम तथा मुद्रित संख्या अंकित करना अनिवार्य होगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन के लिए प्रचार-प्रसार की सामग्री में मुद्रित किये जाने वाला मैटर आदर्श आचार संहिता के दायरे में रहेगा।

बैठक में मास्टर ट्रेनर्स ने बताया कि किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री जैसे हैंडबिल, पम्पलेट, पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स आदि को छापने के लिए संबंधित व्यक्ति द्वारा मुद्रक को घोषणा पत्र भरकर ही आर्डर दिया जायेगा। मास्टर ट्रेनर ने मुद्रकों सलाह दी है कि बिना घोषणा पत्र वाले प्रिंटिंग आर्डर वे ना लें। बैठक में आगे बताया गया कि प्राचार सामग्री छापने के 72 घंटे के अंदर मुद्रित सामग्री के तीन सेट और प्रकाशक की घोषणा को जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी मुद्रकों की होगी। इस दौरान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने पर दंडात्मक कार्यवाही भी की जायेगी।

लाभ पहुंचता देखकर मैं भावुक हो जाता हूं क्योंकि मैं उनसे अलग नहीं हूं और आप ही मेरा परिवार हैंः मोदी

प्रधानमंत्री ने (पीएम-सूरज) राष्ट्रीय पोर्टल का वर्चुअल शुभारंभ किया

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोज़गार आधार जनकल्याण (पीएम-सूरज) राष्ट्रीय पोर्टल का वर्चुअल शुभारंभ किया। साथ ही देश के वंचित वर्गों के एक लाख उद्यमियों का ऋण सहायता स्वीकृत किया। शहीद स्मारक भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में सम्मान किया गया। साथ ही अंत्योदय स्वरोजगार योजना से लाभान्वित हितग्राहियों को ऋण राशि का वितरण किया गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से अपना संबोधन दिया। मंत्री केदार कश्यप ने

संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय गणतंत्र विभिन्नताओं से पूर्ण है, ऐसे में समाज के हर वर्ग का सहारा बनकर राष्ट्रीय विकास की रूपरेखा निर्धारण संकल्पित व साहसिक नीतियों से ही संभव होती है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश के हर भू-भाग में बसे वंचित परिवारों को सरकार की योजनाओं से जोड़कर राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल करने जो मार्गदर्शन दिया है, उसके अधीन विगत 10 वर्षों में सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय ने समावेशी मॉडल पर तेजी से काम किया है। इसके लिए अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सफाई कर्मचारियों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है और इनके सशक्तिकरण हेतु रियायती ब्याज दर पर वित्तीय सहायता सहित संपूर्ण मार्गदर्शन की सुविधा प्रदान की जा रही है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.